

राष्ट्रीय

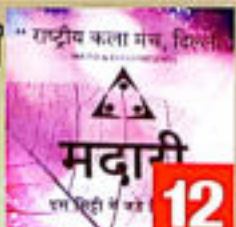
छात्रशक्ति

वर्ष 37 ■ अंक 8 ■ फरवरी, 2017 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 36



राजपथ बना शक्तिपथ

राष्ट्रीय चेतना
जगाएगा
'मदारी'



12

वर्तमान परिदृश्य में
महिला दिवस
की प्रासंगिकता



17

शिक्षा-परिवर्तन :
हमारी
अवधारणा



21

परिषद-गतिविधियाँ



दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अभावपि की दो-दिवसीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यशाला में सम्मिलित अभावपि के राष्ट्रीय पदाधिकारी



मंगलुरु में अम्बेडकर जी की जयन्ती पर हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम 'समरसता से राष्ट्रीयता की ओर'

इस अंक में...



राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 37, अंक 8
फरवरी, 2017

संपादक-मण्डल :

आशुतोष
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :

राष्ट्रीय छात्रशक्ति
छात्रशक्ति भवन
26 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
वेबसाइट : www.abvp.org

✉ chhatrashakti.abvp@gmail.com

📘 www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti

🐦 www.twitter.com/chhatrashakti

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली-110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

- 4 संपादकीय
- 6 राजपथ बना शक्तिपथ
- 8 जय हिन्द की सेना
- 12 राष्ट्रीय चेतना जगाएगा 'मदारी' : सौरभ उनियाल
- 14 कुटीतियों पर प्रहार करना युवाओं का कर्तव्य : सुनील आंबेकर
- 17 वर्तमान परिदृश्य में महिला दिवस की प्रासंगिकता
- 20 अभाविप ने बुलंद किया राष्ट्रवादी शक्तियों का हौसला : रघुवर दास
- 21 शिक्षा-परिवर्तन : हमारी अवधारणा
- 25 सशक्त महिला-सशक्त राष्ट्र का आधार है : ममता यादव
- 28 देशभर में मनाई गई नेताजी सुभाष जयन्ती
- 28 सामाजिक समरसता के प्रतीक थे बाबा साहेब : विनय बिदरे
- 29 परिचर्चा : बजट में शिक्षा-क्षेत्र और युवाओं की स्थिति
- 31 दो-दिवसीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यशाला दिल्ली में संपन्न
- 32 अमेरिका में ट्रम्प सरकार और भारत पर प्रभाव
- 34 ऐसे थे अपने दीनदयाल जी

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

हर भाषा का अपना एक संसार होता है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होती, बल्कि उसके साथ संस्कारों की एक पूरी परम्परा जुड़ी होती है। वह अपने बोलनेवालों को न केवल संवाद का माध्यम उपलब्ध कराती है बल्कि अपने पर्यावरण की समझ और स्थानीय रीतियों-मान्यताओं के आलोक में दुनिया को देखने-परखने की दृष्टि भी प्रदान करती है।

राष्ट्रीय और स्थानीय पहचान की सबसे जीवंत प्रतीक होने के बाद भी भाषा के बोलनेवाले उसका प्रयोग बंद कर दें तो यह विचारीय है। यह और भी चिंतनीय हो जाता है जब भारत-जैसा जीवंत लोकतंत्र अपनी ही जनता को अपनी ही भाषा में न्याय देने से इनकार कर दे। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है।

उच्च न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में और सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी में कार्यवाही की मांग दशकों से ठंडे बस्ते में थी। सर्वोच्च न्यायालय तो इसे ठुकरा ही चुका है। ऐसे में यह ख़बर संतोष देनेवाली है कि संबंधित संसदीय समिति ने आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में न्याय प्रदान किए जाने की संस्तुति की है।

मामला केवल न्यायालय का ही नहीं है। रोज़गार की भाषा के रूप में अंग्रेज़ी के आधिपत्य ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनी जकड़ बना ली है। इस वर्चस्व के चलते जहाँ छोटे समुदायवाली बोली-भाषाएँ दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, वहीं समृद्ध साहित्यिक परम्परावाली आधिकारिक भाषाओं के समक्ष भी कोई कम चुनौती नहीं है।

इससे उत्पन्न समरूपता के दवाब में स्थानीय बोली-भाषाओं की कहावतें, मुहावरे, लोक-साहित्य और देशज शब्दों की दुनिया सिमटती जा रही है। साथ ही सिकुड़ रहा है अपने पर्यावरण के प्रति अपनेपन का भाव। बदलता मौसम और मानव के अन्य प्राणियों के साथ बढ़ते संघर्ष की जड़ में स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत विकसित हुए जीवन-मूल्यों का क्षरण ही है। यह पूरी तरह सच है कि कोई भी अपरिचित भाषा स्थानीय जीवन-मूल्यों के संरक्षण का माध्यम नहीं बन सकती। पहचान और पर्यावरण की दोहरी चुनौती से पार पाने के लिये भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान देना ही होगा।

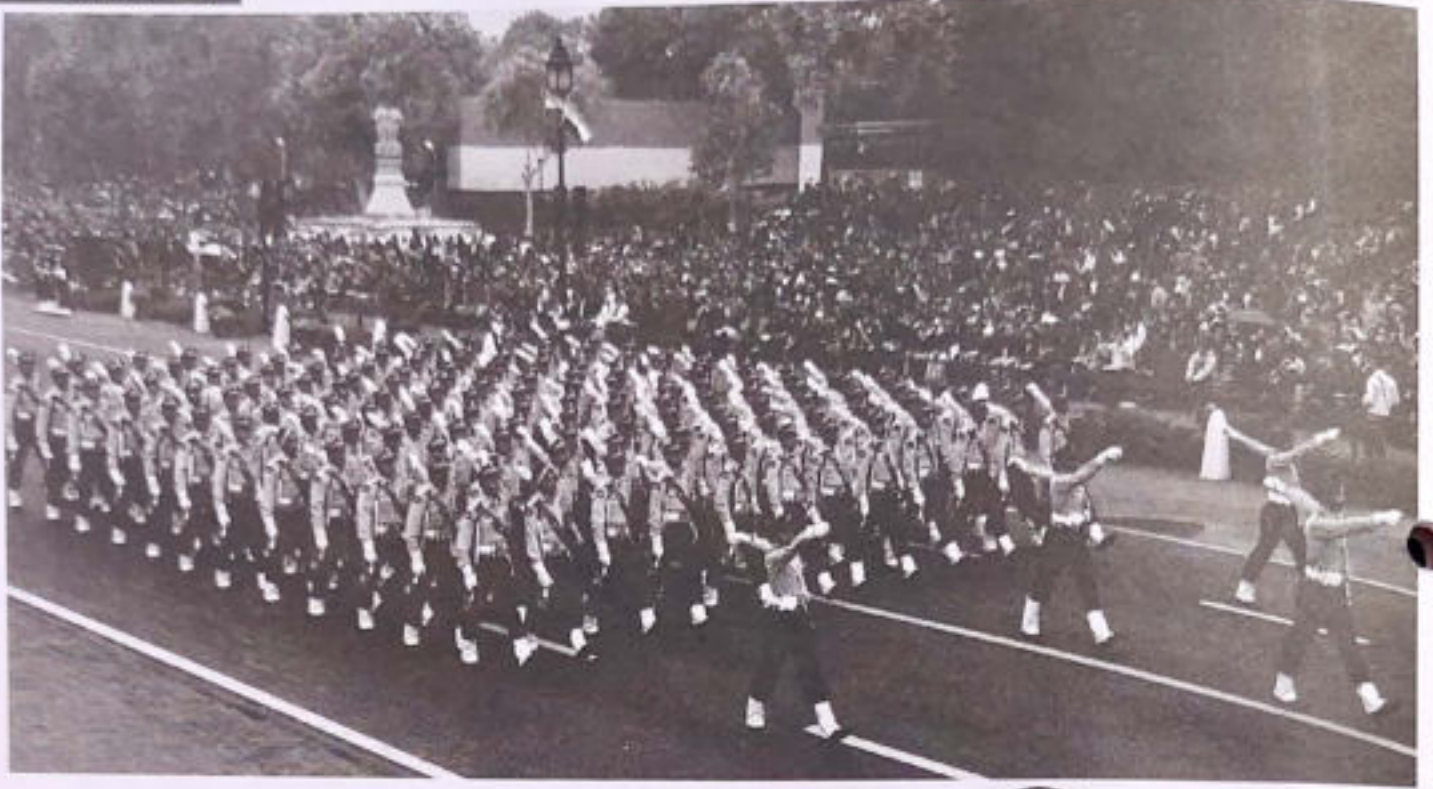
अभाविक की इस चिन्ता को समेटे हुए यह अंक आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें एक ओर सामरिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाते भारत का वर्णन है तो दूसरी ओर सामाजिक

समरसता, कुरीतियों पर प्रहार, नारी का सम्मान और भारत व भारतीयता पर केन्द्रित मूल्यपरक शिक्षा पर गंभीर सामग्री है।

पाँच राज्यों में विधानसभा के चुनाव जहाँ लोकतंत्र के उत्सव के रूप में जारी हैं, इनका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा। होली की पूर्व संध्या पर आनेवाले परिणाम दूरगामी प्रभाव छोड़ेंगे। चुनावी समर में चले आरोप-प्रत्यारोपों के दौर से निकलकर होली का महापर्व सामाजिक सद्भाव का आधार बने, इस शुभकामना के साथ,

आपका,

संपादक



राजपथ बना शक्तिपथ

■ प्रदीप शर्मा व अवनीश राजपूत

सदियों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद हासिल हुई आजादी तथा देश में गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का उत्साह भारतीय जनमानस की रगों में लहू बनकर आज भी दौड़ रहा है। यही वजह है कि लोकतंत्र की जीवंतता का परिचय देने के लिए आज भी गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर आयोजित होनेवाले परेड को देखने के लिए लोगों का उत्साह चरम पर रहता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी में कड़ाके की सर्दी और रिमझिम बारिश के बावजूद 68वें गणतंत्र दिवस की परेड को देखने भारी संख्या में जनसमूह उमड़ा। विजय चौक से ऐतिहासिक लाल किले तक दोनों ओर उत्साही जनता का विशाल हुजूम इसकी गवाही दे रहा था।

एक तरफ सैन्य एवं रक्षा-उपकरणों, सेना के तीनों अंगों की विविध टुकड़ियों की कदम ताल, देशभर की सांस्कृतिक विरासत

और विविध योजनाओं एवं उपलब्धियों की झलक दिखानेवाली झाँकियाँ, जांबाज बच्चों के कारनामे, लोक नर्तकों की टोलियाँ और स्कूली बच्चों के दस्तों ने अपनी मौजूदगी से राष्ट्रीय पर्व को यादगार बना दिया। वहीं, गणतंत्र दिवस परेड में मेकैनाइज़्ड इन्फैन्ट्री रेजीमेंट, बिहार रेजीमेंट, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, गोरखा राइफल्स और पंजाब रेजीमेंटल सेंटर, सिख रेजीमेंटल सेंटर, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, क्षेत्रीय सेना, सिख लाइट इन्फैन्ट्री के संयुक्त बैंड ने सधे कदमों के साथ प्रस्तुति दी। अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों, विमानों और भारतीय सैनिकों के दस्तों ने देश के किसी भी चुनौती से निपट सकने की ताकत का अहसास कराया। इन सबके बीच सबसे अंत में रोमांच से भर देनेवाले वायुसेना के अत्याधुनिक विमानों को राजपथ के ऊपर से हैरत अंगेज कारनामों के साथ उड़ान भरते देखकर उन विमानों की ताकत के साथ ही वायुसेना के पायलटों का हुनर और जांबाजी

का अहसास अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीयता से भरपूर रहा।

इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि আবুঘাबी के शहजादे मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान रहे और गणतंत्र दिवस की इस परेड में यूएई के सैनिकों की एक टुकड़ी ने अपने देश के ध्वज के साथ हिस्सा लिया। इस दस्ते में 149 जवान शामिल थे, जिसमें 35 संगीतकार रहे। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा दल (एनएसजी) ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। काली वर्दी में लगभग 60 कमांडो के एक दल ने राजपथ पर मार्च किया और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सलामी दी। एनएसजी की एंटी-हाइजैकिंग वैन 'शेरपा' भी परेड में शामिल की गई। शेरपा बुलेट-प्रूफ बख्तरबंद वाहन है, जिसमें किसी भी विस्फोट को सहने और पानी के भीतर चलने की क्षमता है।

भारतीय नौसेना ने परेड के दौरान स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस चेन्नई और स्वदेश-निर्मित कालवारी क्लास स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का प्रदर्शन किया। नौसेना में फाक्सटोट-क्लास की पनडुब्बी आईएनएस कालवारी को शामिल किए जाने को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान मरीन कमांडोज़ ने मार्च भी किया। प्रदर्शन में लंबी दूरी के पी8-आई समुद्री निगरानी विमान के मॉडल को भी शामिल किया गया। इसके अलावा देश के हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस और एयरबर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (ईडब्ल्यू एंड सी) ने गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार अपनी ताकत दिखाई।

आसमान में बदली छाप रहने के बावजूद 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर तीन लड़ाकू जेट विमानों ने राजपथ पर दर्शकों को हैरत में डाल दिया। जबकि देश में विकसित अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तेजस पहली बार परेड में शामिल हुआ। आपको बता दें कि तेजस को जुलाई 2016 में भारतीय वायुसेना के 45वें स्काइन में शामिल किया गया था। इसके अलावा परेड में स्वदेश-निर्मित तोप 'धनुष' का पहली बार प्रदर्शन किया गया। जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री द्वारा निर्मित 155 मिमी की इस तोप की लागत 14.50 करोड़ रुपये है। यह भारत द्वारा 1980 के दशक में खरीदे गए बोफोर्स तोपों का उन्नत रूप है। टी-90 भीष्म-टैंकों, इंफैंट्री कम्बैट हवीकल बीएमपी-2के, वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति, सीबीआरएन रीकान्सन्स हवीकल को भी परेड में शामिल किया गया। वहीं, देश में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन

(डीआरडीओ) को उसके आविष्कारों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। लेकिन पहली बार डीआरडीओ का अपना एडवांस्ड टड आर्टिलरी गन सिस्टम और मध्यम क्षमतावाले राडार 'अरुद्र' को प्रदर्शित किया गया। राजपथ पर बीएसएफ का ऊँट दस्ता भी राजसी शान के साथ परेड में शामिल हुआ। यह दस्ता बीकानेर रॉयल फोर्स की विरासत को संजोए हुए था।

हालांकि, हर गणतंत्र दिवस पर हमें देश की सैन्य शक्ति, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन देखने को मिलता है। हम भी उनके यशोगान में कोई कोताही नहीं करते हैं। सेना के अत्याधुनिक हथियार, सेनाओं की रंग-बिरंगी मनभावन टुकड़ियाँ और हवा में कलाबाजी करते, तिरंगे के रंग बिखरते हुए लड़ाकू विमानों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। देखकर भरोसा मजबूत होता है कि हमारी सेनाएँ देश की सुरक्षा करने के लिए न केवल सक्षम हैं, बल्कि दुनिया में हमारा देश एक ताकतवर सैन्य शक्ति बन गया। परन्तु बजट आते ही यह भरोसा धूमिल होने लगता है। हालांकि पिछले तीन सालों में रक्षा-बजट में औसत 10% बढ़ोत्तरी हुई है। रक्षा-क्षेत्र के लिए वर्ष 2011-12 में 1.64 लाख करोड़, 2012-13 में 1.78 लाख करोड़, 2013-14 में दो लाख करोड़, और 2014-15 में 2.20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में था। वर्ष 2015-16 में रक्षा-बजट 2.46 लाख करोड़ रुपए का था जो वर्ष 2016-17 में 93% बढ़ोत्तरी के साथ 2.56 लाख करोड़ रुपये का हो गया। पर आश्चर्य की बात यह है कि इसमें रक्षा का पूंजी-व्यय 2015-16 के 94,588 करोड़ रुपए की तुलना में घटकर 86,340 करोड़ रुपए रह गया। दुनियाभर में देश का खर्च उसके सकल घरेलू के अनुपात (जीडीपी) में आंका जाता है। इस लिहाज से देश का सैन्य व्यय उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता। 2016-17 में पेंशन-व्यय को निकाल दें, तो यह सैन्य व्यय जीडीपी का 1.72% है। यह देखते हुए इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत के सामने जो चुनौतियाँ और खतरे हैं, उन्हें देखते हुए सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यह आवंटन बेहद कम है। एक तरफ सेना में हथियारों और गोला-बारूद की भारी कमी है, तो दूसरी तरफ अरसे से रक्षा मंत्रालय अपना पूरा बजट इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है। उस पर तुरंत यह है कि लुटियंस जोन के कुछ छद्म बुद्धिजीवी रक्षा बजट में कटौती की बात करते रहते हैं।

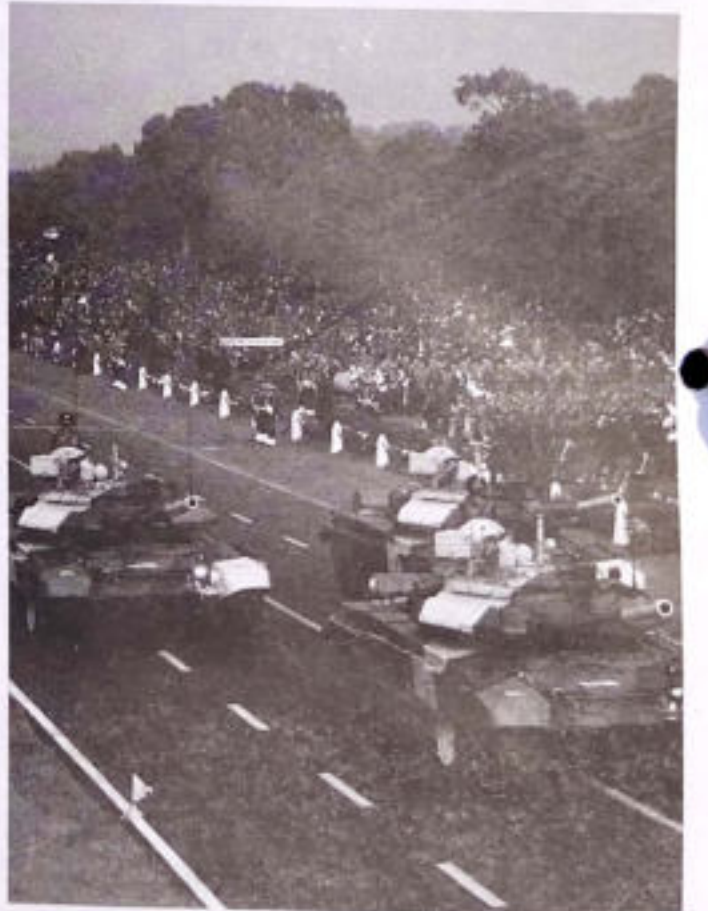
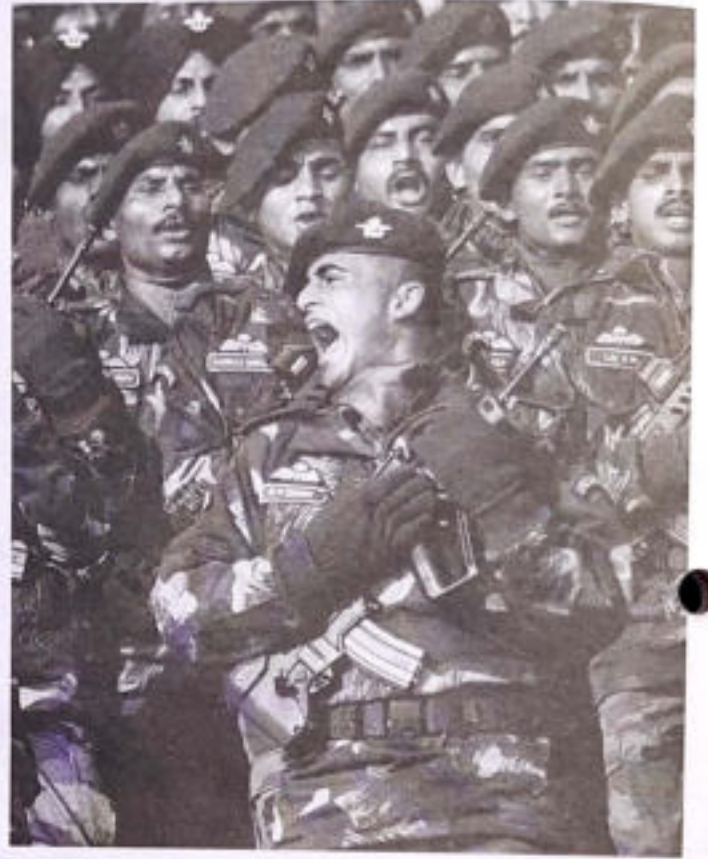
आवरण-कथा

जय हिन्द की सेना

■ अवनीश राजपूत

भारतीय सेना का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यताओं के विकास के साथ विकसित हुआ है। भारत के सेनानियों की गौरवगाथा यहाँ के महाकाव्यों से लेकर लोकगीतों तक में सुनी व समझी जा सकती है। वैदिककालीन देवासुर संग्राम, रामायण और महाभारत-जैसे महान युद्ध समाज के शौर्य के प्रतीक कहे जा सकते हैं। उत्तर काल में मगध का विशाल शासन, गुप्त काल का साम्राज्य-विस्तार, ललितादित्य का विजय-अभियान भारतीय सेना की भव्यता का प्रमाण है। यह भारत की शक्ति-उपासना ही है जिसने महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, बाजीराव और लाचिंत बरफुकन-जैसे सेनानायक उत्पन्न किये। प्रथम विश्वयुद्ध में शामिल तकरीबन बीस लाख एवं द्वितीय विश्वयुद्ध में चालीस लाख भारतीय सिपाहियों ने अपने अदम्य रणकौशल से सम्पूर्ण विश्व की रक्षा की। यह वही भारतीय सेना थी जिसका पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण 1776 में ईस्ट इण्डिया कंपनी ने कलकत्ता में किया था। आज भारतीय सेना के देशभर में 53 कैंटोनमेंट और 9 आर्मी बेस हैं। असम रायफलस भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है।

भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक माना जाता है। इस समय भारत के पास कुल 13,25,000



सशस्त्र सेना 21,43,000 रिजर्व सेना और 13,01,000 अर्धसैनिक बल है। भारतीय सेना के तीनों अलग-अलग हिस्सों की बात करें तो वायुसेना के पास 2,086 एयरक्राफ्ट, 646 हेलीकॉप्टर, 19 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड विंग में लड़ाकू विमानों की संख्या 809 है जबकि अन्य लड़ाकू विमान 679 हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की संख्या की बात करें तो इस समय ट्रेनर एयरक्राफ्ट 318 और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 857 के करीब हैं। जबकि, भारतीय थल सेना में युद्धक टैंकों की संख्या इस समय 6464, 6704 बख्तरबंद लड़ाकू विमान, 290 स्वचालित बंदूक वाहन, 7414 तोपखाने और 292 रॉकेट लांचर प्रणाली मौजूद है। फिलहाल, भारतीय नौसेना के बेड़े में 340 मर्चेट मरीन शक्ति, 7 मेजर पोर्ट, 295 फ्लीट स्ट्रेंथ, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। वहीं, 14 सबमरीन, 14 युद्धपोत, 10 विध्वंसक, 6 माइन वारफेयर क्राफ्ट और 135 पेट्रोल क्राफ्ट भी नौसेना की शक्ति को बढ़ा रहे हैं।

भारतीय सेना के प्रमुख युद्धक हथियार

तेजस



सिंगल और डबल सीटर लड़ाकू विमानों की पाँचवीं पीढ़ी के विमानों में भारत की ओर से विकसित और

भारत में ही निर्मित तेजस पूरी तरह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में शामिल हो चुका है। स्टील्थ तकनीक से लैस ये विमान भारत की हर जरूरत को पूरा करेगा, जो भारत की वायुसेना और जलसेना— दोनों के ही उपयोग के लिए है। यह हल्का विमान है और बेहद कम समय में ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस कम ऊँचाई में उड़ान भरकर महज 15 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी शहर को तहस-नहस कर सकता है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी उसका किसी भी मौसम और किसी भी समय उड़ान भरकर हमला करने की है, जिससे भारत पड़ोसी देशों पर किसी भी युद्ध के शुरूआती चरण में भी बढ़त बना लेगा। इसे किसी भी मिसाइल से नहीं गिराया जा सकेगा।

सुखोई-30

यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इण्डियन एयरफोर्स को 21वीं

शती के हिसाब से पारिभाषित कर सकता है। रूस में निर्मित



सुखोई-30 जेट फाइटर को दुनिया में बेहतरीन एयर-क्राफ्ट्स में गिना जाता है। इसकी लम्बाई 21.93 मीटर और चौड़ाई 14.7 मीटर है।

बगैर हथियार के इसका वजन 18 हजार चार सौ किलोग्राम है। हथियार के साथ इसका वजन 26 हजार किलोग्राम से अधिक हो सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2,100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह तीन हजार किलोमीटर तक की गहराई में जाकर हमला कर सकता है। दो शक्तिशाली इंजनवाला यह विमान किसी भी तरह के प्रतिकूल मौसम में उड़ान भरकर हवा से हवा सहित हवा से ज़मीन पर हमला करने में अपनी कुशलता को प्रमाणित कर चुका है।

ब्रह्मोस



ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, जिसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल

महज 290 किमी तक ही वार करने में सक्षम है, लेकिन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में दुनिया की उन गिनी-चुनी मिसाइलों में से एक है, जिसे जल, थल, वायु कहीं से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल होने का तमगा प्राप्त है, जो राडार की पकड़ में नहीं आती और पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूत कर सकती है। यह मिसाइल सिर्फ 10 मीटर की ऊँचाई पर उड़ने की भी क्षमता रखती है।

भीष्म टैंक

दुश्मन से सीधी लड़ाई के लिए यह टैंक भारत के ब्रह्मास्त्र की

सशस्त्र सेना 21,43,000 रिजर्व सेना और 13,01,000 अर्धसैनिक बल है। भारतीय सेना के तीनों अलग-अलग हिस्सों की बात करें तो वायुसेना के पास 2,086 एयरक्राफ्ट, 646 हेलीकॉप्टर, 19 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, फिक्स्टड विंग में लड़ाकू विमानों की संख्या 809 है जबकि अन्य लड़ाकू विमान 679 हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की संख्या की बात करें तो इस समय ट्रेनर एयरक्राफ्ट 318 और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 857 के करीब हैं। जबकि, भारतीय थल सेना में युद्धक टैंकों की संख्या इस समय 6464, 6704 बख्तरबंद लड़ाकू विमान, 290 स्वचालित बंदूक वाहन, 7414 तोपखाने और 292 रॉकेट लांचर प्रणाली मौजूद है। फिलहाल, भारतीय नौसेना के बेड़े में 340 मचेंट मरीन शक्ति, 7 मेजर पोर्ट, 295 फ्लीट स्ट्रेंथ, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। वहीं, 14 सबमरीन, 14 युद्धपोत, 10 विध्वंसक, 6 माइन वारफेयर क्राफ्ट और 135 पेट्रोल क्राफ्ट भी नौसेना की शक्ति को बढ़ा रहे हैं।

भारतीय सेना के प्रमुख युद्धक हथियार

तेजस



सिंगल और डबल सीटर लड़ाकू विमानों की पाँचवीं पीढ़ी के विमानों में भारत की ओर से विकसित और

भारत में ही निर्मित तेजस पूरी तरह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में शामिल हो चुका है। स्टील्थ तकनीक से लैस ये विमान भारत की हर ज़रूरत को पूरा करेगा, जो भारत की वायुसेना और जलसेना— दोनों के ही उपयोग के लिए है। यह हल्का विमान है और बेहद कम समय में ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस कम ऊँचाई में उड़ान भरकर महज 15 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी शहर को तहस-नहस कर सकता है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी उसका किसी भी मौसम और किसी भी समय उड़ान भरकर हमला करने की है, जिससे भारत पड़ोसी देशों पर किसी भी युद्ध के शुरूआती चरण में भी बढ़त बना लेगा। इसे किसी भी मिसाइल से नहीं गिराया जा सकेगा।

सुखोई-30

यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इण्डियन एयरफोर्स को 21वीं

शती के हिसाब से पारिभाषित कर सकता है। रूस में निर्मित



सुखोई-30 जेट फाइटर को दुनिया में बेहतरीन एयर-क्राफ्ट्स में गिना जाता है। इसकी लम्बाई 21.93 मीटर और चौड़ाई 14.7 मीटर है।

बगैर हथियार के इसका वजन 18 हजार चार सौ किलोग्राम है। हथियार के साथ इसका वजन 26 हजार किलोग्राम से अधिक हो सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2,100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह तीन हजार किलोमीटर तक की गहराई में जाकर हमला कर सकता है। दो शक्तिशाली इंजनवाला यह विमान किसी भी तरह के प्रतिकूल मौसम में उड़ान भरकर हवा से हवा सहित हवा से ज़मीन पर हमला करने में अपनी कुशलता को प्रमाणित कर चुका है।

ब्रह्मोस



ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, जिसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल

महज 290 किमी तक ही वार करने में सक्षम है, लेकिन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में दुनिया की उन गिनी-चुनी मिसाइलों में से एक है, जिसे जल, थल, वायु कहीं से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल होने का तमगा प्राप्त है, जो राडार की पकड़ में नहीं आती और पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूत कर सकती है। यह मिसाइल सिर्फ 10 मीटर की ऊँचाई पर उड़ने की भी क्षमता रखती है।

भीष्म टैंक

दुश्मन से सीधी लड़ाई के लिए यह टैंक भारत के ब्रह्मास्त्र की

तरह है। इससे पाँच किलोमीटर के दायरे तक प्रहार किया जा सकता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि इस टैंक पर किसी भी

तरह के रासायनिक, जैविक या रेडियोएक्टिव हमले का असर नहीं होता। भीष्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाए और उससे निकलनेवाली विकिरणें टैंक के अंदर बैठे सिपाहियों को हानि न पहुँचा सकें। 48 टन वजनी इस टैंक में 125 एमएम की स्मूथबोर गन है। इसके साथ ही, इसमें 12.7 एमएम की मशीनगन भी है जिसे मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। कमांडर इसे अंदर बैठकर रिमोट से भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसा कहा गया कि भारत का टी-90एस रूस के टी-90ए का डाउनग्रेड वर्जन है लेकिन भारत ने इसे इजरायली, फ्रांसीसी और स्वीडिश सब सिस्टम्स से लैस कर रूसी वैरियंट से भी बेहतर कर दिया है।

अर्जुन टैंक



यह टैंक भारतीय वैज्ञानिकों की लगातार तीन दशकों तक की गयी अथाक मोहनता का परिणाम है। इस टैंक को भारतीय

सेना में वर्ष 2009 में शामिल किया गया। समय के साथ ही इसमें परिवर्तन कर इसे और भी क्षमतावान् बनाया गया। इस टैंक में रात और दिन चौबीसों घंटे देखने के लिए नाईट विजन सर्विलांस की सुविधा दी गई है। इसमें अत्याधुनिक ऑटोमैटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से रात हो या दिन, यह ऑटोमैटिक तरीके से किसी भी अस्थिर लक्ष्य को भी बेहद आसानी से निशाना साधकर नष्ट कर सकता है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इस टैंक के जरिये अब भारतीय सेना मिसाइलें भी दाग सकती है। यह तकनीक इसे दुनिया के बाकी टैंकों से बेहतर और ज्यादा ताकतवर भी बनाती है। इस टैंक में अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन को भी लगाया गया है जिसके

जरिये यह टैंक बेहद आसानी से आसमान में उड़ रहे दुश्मन के किसी भी हेलीकॉप्टर को मिनटों में ज़मीन पर गिरा सकता है। यह टैंक अपने रास्ते में आनेवाली किसी भी लैंड माइंस को निकालकर बाहर कर सकता है और अपना तथा अपनी सेना का रास्ता बेहद आसानी के साथ सुरक्षित कर सकता है।

राफेल



राफेल आसमान से दुश्मनों के छके छुड़ा देनेवाला एक बहुपयोगी लड़ाकू विमान है। इसकी लंबाई 15.27 मीटर है और इसमें ए

या दो पायलट बैठ सकते हैं। जानकार बताते हैं कि राफेल ऊँचे इलाकों में लड़ने में माहिर है। राफेल एक मिनट में 60 हजार फुट की ऊँचाई तक जा सकता है। हालांकि अधिकतम भार उठाकर इसके उड़ने की क्षमता 24,500 किलोग्राम है। विमान में इंधन-क्षमता 4,700 किलोग्राम है। राफेल की अधिकतम रफ्तार 2,200 से 2,500 किमी प्रतिघंटा है और इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। इसमें 130 एमएम की एक गन लगी होती है जो एक बार में 125 राउंड गोलियाँ निकाल सकती है। इसके अलावा इसमें घातक एमबीडी, एमआइसी, एमबीडी मेटेओर, एमबीडी अपाचे, स्टोर्म शैडो एससीएएलपी मिसाइलें लगी रहती हैं। इसमें थाले आरबीई-2 रडार और थाले स्पेक्ट्रा वारफेयर सिस्टम लगा होता है। साथ ही इसमें ऑप्टिक सेन्सोर फ्रंटल इंफ्रा-रेड सर्च और ट्रैक सिस्टम भी लगा है।

आईएनएस विक्रमादित्य



इस विमानवाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 44,500 टन क्षमतावाले इस युद्धपोत की लंबाई

283.1 मीटर और ऊँचाई 600 मीटर है। इसपर डेकों की संख्या 22 है। कुल मिलाकर इसका क्षेत्र तीन फुटबाल मैदान के बराबर है। इस पोत में कुल 22 तल हैं और 1,600 लोगों को ले जाने की क्षमता है। यह 32 नॉट (59 किमी/घंटा) की रफ्तार से

गश्त करता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। यह 24 मिग-29KUB ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा परमाणु क्षमतायुक्त पनडुब्बी आईएनएस चक्र-2 नौसेना के बड़े हथियारों में शुमार है। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। यह तीन महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। नेरपा पनडुब्बी की अधिकतम गति 30 समुद्री मील है और ये आठ टरपीडो से युक्त है। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के अनुसार यह अनुबंध 90 करोड़ डॉलर से ज्यादा का है।

हेलिना



यह 'नाग' का हेलीकॉप्टर से दागा जा सकने वाला संस्करण है और

इसे रक्षा-अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईजीएमडीपी) के तहत विकसित किया है। नाग मिसाइल की विशेषता है कि यह टॉप अटैक-फायर एंड फोरगेट और सभी मौसम में फायर करने की क्षमता से लैस है। हमला करने के लिए 42 किग्रा वजन की इस मिसाइल को हवा से ज़मीन पर मार

करने के लिए हल्के वजन के हेलीकॉप्टर में भी लगाया जा सकता है। इन्फैंट्री कॉम्बेट व्हीकल बीएमपी-2 नमिका से भी इस मिसाइल का दागा जा सकेगा।

'पिनाका'



यह एक ऐसी हथियार-घणाली है जिसका लक्ष्य मौजूदा तोपों के लिए 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर

पूरक व्यवस्था करना है। कम तीव्रतावाली युद्ध-जैसी स्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और तेजी से दागने की क्षमता सेना को बढ़त दिलाती है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मल्टी-बैरल रकेट लन्चर में अनेक विशेषताएँ हैं।

(लेखक, राष्ट्रीय छात्रशक्ति के संपादक मण्डल के सदस्य हैं)

इसरो ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में जमाई अपनी धाक

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 15 फरवरी को एक साथ 104 सैटेलाइट कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कराकर एक नया इतिहास रच दिया है। बता दें कि अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) भी आज तक एकसाथ इतने सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सका है। इस मिशन के जरिये इसरो ने अपनी शानदार क्षमता का प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही अंतरिक्ष बाजार में अपनी धाक भी जमा ली है। इसी मिशन के जरिये उसने कार्टोसेट-2 शृंखला की एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। इसके जरिये देश को मौसम की सूचना से लेकर सड़कों के हाल तक की जानकारी और जमीन उपयोग का पता लगाने तक में मदद मिल सकेगी।

पीएसएलवी के इस सफ़र में भारत के तीन और विभिन्न देशों के 101 अन्य सैटेलाइट शामिल थे। विदेशी सैटेलाइट में से 96 अमेरिका की दो कंपनियों के थे। जबकि इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्वीट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के एक-एक सैटेलाइट शामिल थे। इसरो अब तक 21 विकसित और विकासशील देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। पर कम लागत और छोटी सैटेलाइट लॉन्च करने की बेहतर क्षमता के चलते इसरो आनेवाले दिनों में दुनिया के कई गरीब देशों को भी अपनी सैटेलाइटें लॉन्च करने का मौका दे सकता है। इस मिशन के लिए इसरो ने सिर्फ 23 घंटे का काउंटडाउन कि जो अब तक सबसे संक्षिप्त काउंटडाउन था। आमतौर पर ऐसे मिशन के लिए 52 घंटे तक के काउंटडाउन का समय लगता है।



राष्ट्रीय चेतना जगाएगा 'मदारी' : सौरभ उनियाल

भारतीय शिक्षा-व्यवस्था को केवल डिग्री तक सीमित नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं अतिरिक्तगतिविधियों को भी पठन-पाठन में सम्मिलित करना चाहिए। कला देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में महती भूमिका अदा करती है। हमारे देश की पुरातन व्यवस्था में भी कला का महत्वपूर्ण स्थान था।

साहित्य, संगीत, कला और नाट्य विधा के क्षेत्र में छात्रों के अंदर राष्ट्रीय चेतना भरने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक उत्सव 'मदारी' का आयोजन किया गया। यह उत्सव दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं राष्ट्रीय कला मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। दिनांक 23-25 जनवरी तक तीन दिन चले इस कार्यक्रम में पहले दिन नुक्कड़-नाटक, दूसरे दिन एकल कला प्रस्तुति तथा तीसरे दिन सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण, ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम के पहले दिन यानि 23 जनवरी, 2017 को 13 कॉलेजों की नुक्कड़ नाटक टीमों ने अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्राचीन भारतीय कला, संस्कृति, जनजीवन का बखान किया। समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों के कारणों के साथ-साथ उनके उपायों को भी नाटकों के द्वारा दर्शकों के सामने नाट्य रूप में रखा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा कि आज के छात्रों को अपनी वैचारिक,

सांस्कृतिक एवम् पारिवारिक जड़ों से जुड़े रहने की ज़रूरत है। आज के युवा को अपने वैभवशाली अतीत को पहचानने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी वास्तविक पहचान, ग्रामीण व सांस्कृतिक पहचान को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उस पर गर्व करना चाहिए।

वहीं अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास ने युवाओं को आगे आकर राष्ट्र-निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने युवाओं को अपनी रचनात्मकता को समाज में व्याप्त बुराइयों के निर्मूलन हेतु लगाने का आह्वान किया। वर्तमान समय देश को आगे ले जाने की जिम्मेवारी युवावर्ग की है, छात्रों को अपने पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेना चाहिए, इससे प्रतिभा का विकास होता है।

राष्ट्रीय कला मंच के राष्ट्रीय संयोजक सौरभ उनियाल ने कहा कि अपनी बात लोगों तक पहुँचाने में नृत्य, संगीत, कला, नाटक की अहम भूमिका होती है। वामपंथी छात्र संगठनों ने इसका सहारा लेकर देश की संस्कृति, मान्यताओं और राष्ट्र का



जमकर उपहास किया और दुष्प्रचार किया। हमारी कोशिश है कि हम नये सिरे से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करें और लोगों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विचारों से अवगत करायें। सामाजिक विसंगतियों पर भी इसके माध्यम से प्रहार किया जाएगा। नाटकों के माध्यम से केवल समस्याओं को ही सामने नहीं रखना चाहिये बल्कि समाज को एक उपाय भी उस हेतु प्रेषित करना चाहिए। कला को सकारात्मक दिशा में ले जानेवाली इस पहल को संपूर्ण देश में ले जाया जायेगा।

कला मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नुक्कड़-नाटकों की एक नयी परम्परा का आगाज किया गया है। नाटकों की थीम भारतीय समाज, व्यवस्था, संस्कृति, ग्रामीण जीवन और महिलाओं पर आधारित है। नाटकों में केवल समस्याओं को ही प्रदर्शित नहीं किया गया है, बल्कि उन समस्याओं के समाधान हेतु उपायों का संदेश भी दिया जा रहा है।

कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में उपस्थित श्री गोपाल दत्त ने कहा कि युवाओं के बीच आकर मैं नाटक की आगामी नयी पीढ़ी को देख रहा हूँ। जिस स्फूर्ति के साथ सामाजिक मुद्दों को शैक्षणिक शोध के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है, पेशेवर

कलाकारों को भी इस पद्धति से सीखना चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष अमित तैवर व उपाध्यक्ष प्रियंका छावड़ी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम लोगों को जोड़ने के साथ उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी भरते हैं।

कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न कॉलेजों से आई ग्यारह टीमों ने अपने नाटक का मंचन किया जिसमें लगभग चार हजार बच्चों ने कला-प्रदर्शन व नुक्कड़-नाटकों का लुत्फ उठाया।

राष्ट्रीय कला मंच के दिल्ली प्रांत संयोजक ध्रुव कांडपाल ने कहा कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की जरूरत है। जो संस्कृति अपनी जड़ों से दूर हो जाती है, उसका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। कला को सकारात्मक दिशा में ले जानेवाली इस पहल को संपूर्ण देश में ले जाया जायेगा।

तीन दिनों तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन कांफ्रेंस सेंटर में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ जिसमें दो हजार छात्र मौजूद थे। समापन-कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर व भारतीय जनसंचार संस्थान के निदेशक श्री के.जी. सुरेश मौजूद थे।

समापन-समारोह को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि भारतीय शिक्षा-व्यवस्था को केवल डिग्री तक सीमित नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं अतिरिक्त गतिविधियों को भी पठन-पाठन में सम्मिलित करना चाहिए। कला, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में महती भूमिका अदा करती है। हमारे देश की पुरातन व्यवस्था में भी कला का महत्वपूर्ण स्थान था।

कार्यक्रम के अंतिम दिन में विजेता टीमों जैसे बेहतरीन पटकथा, श्रेष्ठ संगीत प्रस्तुति देनेवाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर गृह अर्थशास्त्र संस्थान, दूसरे स्थान पर आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, तीसरे स्थान पर वोक्शनल स्टडीज कॉलेज की टीम रही। सर्वश्रेष्ठ पटकथा हेतु लेडी इर्विन कॉलेज की नाटक टीम को पुरस्कृत किया गया। छात्र-कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु रौनक आर्यन व अंकित माथुर को पुरस्कृत किया गया। वहीं छात्रा-कलाकारों में शिवानी व तान्या को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया गया।

कुरीतियों पर प्रहार करना युवाओं का कर्तव्य : सुनील आंबेकर

अभाविप द्वारा देशभर में धूमधाम से मनाई गई
स्वामी विवेकानन्द जयन्ती

स्वामी विवेकानन्द की 154वीं जयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा देशभर में धूमधाम से मनाई गयी। इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों में परिषद् द्वारा विवेकानन्द संदेश-यात्रा, शोभायात्रा, संगोष्ठी, वाहन-रैली, छात्रसभा, रक्तदान-शिविर, नशामुक्ति-शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सामान्यज्ञान प्रतियोगिता, भाषण-प्रतियोगिता, कविता, साहित्य-वितरण, मैराथन दौड़ आदि कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इस कड़ी में अभाविप, दिल्ली प्रांत द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में स्वामी विवेकानन्द जयन्ती पर



कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने विवेकानन्द जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्वपटल पर भारतीय संस्कृति का गौरव और मान किसी ने बढ़ाया तो सबसे पहले स्वामी विवेकानन्द थे। विवेकानन्द एक ऐसे क्रान्तिकारी थे जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा से लोगों का हृदय परिवर्तित किया और देश एवं समाज के हित में काम करने के लिए प्रेरित किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार करना युवाओं का कर्तव्य है।



यदि देश में आजादी के 70 साल बाद भी गरीबी और अत्याचार है तो यह काफी चिन्तनीय है। लेकिन इसके लिए दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय युवाओं को आगे आकर इसे दूर करना करना होगा जिसकी शुरूआत वे अपने शैक्षणिक परिसर से करें।

दिल्ली प्रदेश मंत्री भरत खटाना ने बताया कि स्वामी विवेकानन्द जयन्ती के उपलक्ष्य में दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर को स्वामी जी की प्रतिमाओं, झण्डे व बैनरों से सजाकर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कविता, चित्रकला व राष्ट्रभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) द्वारा स्मृति-चिह्न व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष अवनीश मित्तल, डूसू अध्यक्ष अमित तैवर, उपाध्यक्ष प्रियंका चावड़ी, सचिव अंकित सांगवान, विभाग-संयोजक सचिन बैसला भी उपस्थित रहे।

वहीं अभाविप, अरुणाचल प्रदेश द्वारा विवेकानन्द जयन्ती के उपलक्ष्य पर राज्य की ग्यारह इकाइयों में कार्यक्रम आयोजित किए गये जिसमें 2,000 से अधिक छात्र-छात्राएँ शामिल थीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित



विश्वविद्यालय कार्य के राष्ट्रीय प्रमुख श्रीहरि बोरिकर ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। स्वामी जी ने कहा था 'उठो जागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाय रुको मत'। स्वामी जी के उक्त संदेश को आत्मसात कर हमें आगे बढ़ना होगा तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पायेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रश्नोत्तरी-प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।

अभाविप, कोंकण प्रांत द्वारा स्वामी विवेकानन्द जयन्ती को युवा सप्ताह के रूप में मनाया गया जो 12 जनवरी से शुरू होकर 23 जनवरी तक चला। इस कड़ी में रंगोली प्रतियोगिता,



चित्रांकन प्रतियोगिता, परफॉर्मिंग आर्ट प्रतियोगिता, नाट्य कला, खेलकूद आदि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अभाविप के केन्द्रशासित प्रदेश के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेवाल ने कहा कि इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम समाजस्पर्शी है। स्वामी विवेकानन्द खुद फुटबॉल खेलते थे, खेलकूद से हमारा शारीरिक विकास होता है और नाट्य कला से मानसिक विकास। युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक कार्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध मराठी कलाकार आरोह वेलनकर ने कहा कि आनेवाले समय में सांस्कृतिक क्षेत्र में 'युगम यूथ फेस्ट' मील का पत्थर साबित होगा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन अभाविप के अलावा कोई भी संगठन नहीं करता है।

युवा महोत्सव के कार्यक्रम प्रमुख सचिन सारन ने बताया कि इस युवा महोत्सव कार्यक्रम की तैयारी दो महीने पहले शुरू कर दी गई थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता पिछले दो महीनों से दिन-रात लगे रहे। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में मुंबई के 62 महाविद्यालयों के 177 प्रवेशिका और 750 प्रतिभागी शामिल हुए।

स्वामी विवेकानन्द जयन्ती के अवसर पर धौलपुर (राजस्थान प्रांत) अभाविप के द्वारा महाराणा प्रताप विद्यालय में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस दौरान महाराणा एवं इमान्युअल मिशन स्कूल की टीम में तीन पारियों में मैच कराया। विजेता टीम को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर



सम्मानित किया गया। अभाविप राजस्थान के अनुसार प्रदेशभर के 42 जिला-केन्द्रों की प्रत्येक इकाई पर विवेकानन्द जयंती आयोजित किये गये। युवा सप्ताह के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अभाविप, कौशांबी (उ.प्र.) की ओर से सरायअंकिल के सरदार पटेल इंटर कॉलेज में स्वामी विवेकानन्द की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर उनके कार्यों का बखान किया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभा



दिखानेवाले 30 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष रोहित मिश्र ने कहा कि जब तक युवा संगठित नहीं होगा, तब तक भारत विश्व पटल पर आगे नहीं बढ़ सकता। संगठित युवाओं के माध्यम से ही समर्थ देश खड़ा होगा जो दुनिया की सभी समस्याओं के समाधान की गारण्टी होगी। इस अवसर पर जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया, यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की सर्वोच्चता से दस स्थान प्राप्त



करनेवाले के अलावा खेल, विज्ञान, साहित्य, सिनेमा और जीवनी-लेखन के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि अर्जित करनेवाले छात्र-छात्राओं को प्रमाण-पत्र, स्मृति-चिह्न व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।

अभाविप, मध्य भारत द्वारा स्वामी विवेकानन्द जयंती को 'पर्यावरण संरक्षण दिवस' के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री रोहिन राय ने कहा युवाओं को समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द जी के जीवन-चरित्र को रेखांकित करते हुए श्री राय ने कहा लंबी आयु जीना आवश्यक नहीं, विवेकानन्द जी ने मात्र 39 वर्ष की अवस्था में ही विश्व में हिंदू-धर्म का डंका बजा दिया था। हमें स्वामी जी को आदर्श मानकर उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए। इस मौके पर मध्यभारत के प्रांत मंत्री बंटी चौहान ने कहा कि स्वामी जी का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने बताया कि प्रान्त के सभी जिलों के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में वाहन- रैली, शोभायात्रा, वृक्षारोपण एवं संदेश-यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें उज्जैन में 3159, ग्वालियर में 2753, इंदौर में 2753 सहित प्रांत के 34 जिलों में 120 स्थानों पर 16122 छात्र, 3322 छात्राएँ, 534 प्राध्यापक सहित कुल 19,978 विद्यार्थी उपस्थित थे।

वर्तमान परिदृश्य में महिला दिवस की प्रासंगिकता

मनीषा कोठेकर

आज विश्व में महिलाओं की स्थिति के बारे में चिंतन तथा अध्ययन की जो स्थिति है, वह लगातार वैश्विक स्तर पर चल रहे प्रयासों का परिणाम है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। आज विश्व में लगभग हर देश के द्वारा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1910 में अंतरराष्ट्रीय परिषद् में जर्मन कम्युनिस्ट नेता क्लारा झेटकिन ने इस दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करने की सूचना की और उसके बाद यह दिन जागतिक महिला दिन करके विकृत हुआ। क्लारा झेटकीन के द्वारा इसी दिन को चुनने के पीछे इतिहास ऐसा है कि 8 मार्च 1857 में न्यूयॉर्क में कपड़ा तथा वस्त्रोद्योग में काम करनेवाली कामकाजी महिलाओं ने उनकी मांग के लिए बड़ी संख्या में आंदोलन किया, जुलूस निकाला। उनकी मांगें थी 'समान वेतन तथा समान कार्य-संस्कृति'। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिससे इस आंदोलन की बड़ी चर्चा हुई। क्लारा झेटकीन ने इसी दिन को चुना और 1910 के जागतिक परिषद में वह सर्वसम्मति से पारित हो गया।

सन् 1910 की यह परिषद दूसरी महिला परिषद् थी। इसके पहले 1907 में यूरोप के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी

परिषद् का

आयोजन

हुआ था, जिसमें

15 देशों से महिला

प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे

जिसमें भारत से मैडम कामा

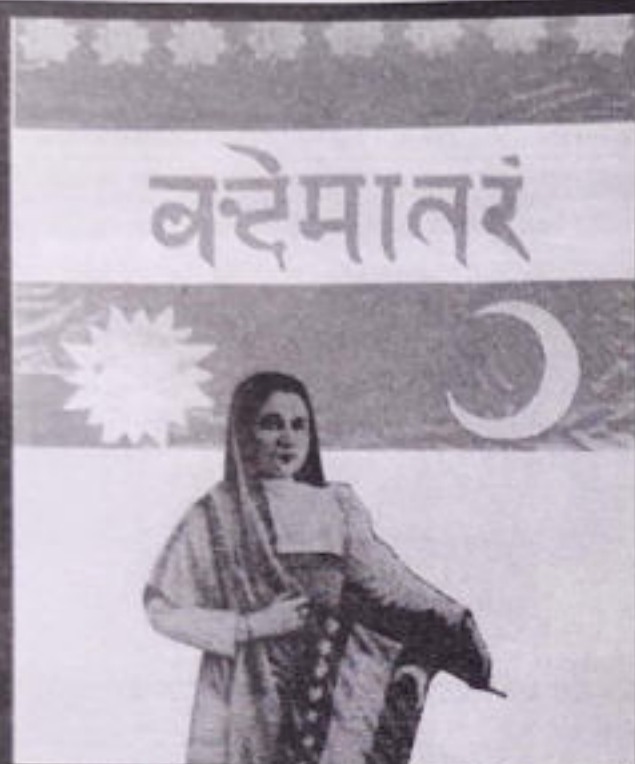
उपस्थित थीं। मैडम भिकाजी कामा ने वहाँ

पर सभी उपस्थित को भगिनीभाव (Sisterhood)

का पालन करने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद द्वितीय महायुद्ध के कारण यह आंदोलन की गति मंद हो गई, लेकिन फिर 60 के दशक में स्त्री-आंदोलन ने जोर पकड़ा और धीरे-धीरे 'महिला दिन' का महत्त्व भी बढ़ते गया।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में देश की मुक्ति-संग्राम में महिलाओं का सहभाग बहुत संख्या में था, साथ ही स्त्री-मुक्ति आंदोलन भी चला। सामाजिक विषयों के साथ ही महिला अपने स्थिति तथा अधिकारों के प्रति भी सजग हुई।

परिणामतः पूरे भारत में छोटे-छोटे तौर पर महिलाओं के गुट बने, संस्थाओं का जन्म हुआ।



यूरोप के स्टुटगार्ड में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषद का आयोजन हुआ था, जिसमें 15 देशों से महिला प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे जिसमें भारत से मैडम कामा उपस्थित थीं। मैडम भिकाजी कामा ने वहाँ पर सभी उपस्थित को भगिनीभाव का पालन करने का प्रस्ताव रखा था।

1927 में मार्गरेट कूझी ने 'ऑल इंडिया वूमैन्स एसोसिएशन' की स्थापना की। 1936 में 'राष्ट्र सेविका समिति' का जन्म हुआ। 1918-22 तक डॉ. ऐनी बेसेंट द्वारा 'मताधिकार आंदोलन' चलता रहा और 1947 के दरम्यान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटीय प्रोवीन्स पेशावर में मुस्लिम महिलाएँ मताधिकार के मांग को लेकर बड़ी संख्या में एकत्रित हुईं। इसका परिणाम भारतीय संविधान में महिलाओं का मताधिकार तथा चुनाव में खड़ा रहने का अधिकार प्राप्त होने में हुआ।

महिलाओं ने विभिन्न आंदोलन में सक्रिय सहभाग लिया जैसे महाराष्ट्र में 1940-48 के दौरान साठ कपड़ा-मिलों के आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं ने किया तो बंगाल प्रांत में 1944 में भाग लिया, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व बारमानी नामक प्रसिद्ध महिला ने किया।

सन् 1947 में स्वातन्त्र्य के साथ हुए बँटवारा से जो हिंसाचार हुआ, उसकी रोकथाम में महिलाओं का बड़ा सहभाग

रहा। इस प्रकार अनेक सामाजिक आंदोलनों में वे सक्रिय रहीं, परंतु राजकीय क्षेत्र में उसका सहभाग कम रहा। 1952-71 में लोकसभा में मतदान का प्रतिशत 45 था जिसमें महिलाओं का योगदान 27 प्रतिशत था। आज 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में उनकी उपस्थिति तथा कार्य लक्षणीय है, अपितु लोकसभा तथा राज्यसभा में आज भी प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम है।

सन् 1960 के अंत में कई सारे सामाजिक विषयों के आंदोलनों का नेतृत्व महिलाओं ने किया, फिर वह शहिदा मिल आंदोलन हो या चिपको आंदोलन, इसके सहभाग से महिलाओं का अपनी समस्याओं की तरफ ध्यान केन्द्रित होने लगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश इत्यादि राज्यों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शराबबंदी आंदोलन चलाया।

सन् 1972 में गुजरात में इरन भट्ट ने असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं को एकत्रित किया। SEWA नाम का संगठन बनाया और फिर यह अन्य राज्यों में भी फैलता गया। 1974 में 'समानता की ओर' - यह रिपोर्ट प्रसिद्ध हुआ जो महिलाओं की स्थिति को तथा उनकी मांगों तथा उमंगों को उजागर कर रहा था।

सन् 1975 में उन्होंने यह वर्ष 'महिला वर्ष' तथा बाद में 1975-1985 यह 'महिला दशक' नाम से घोषित किया और 1975 के महिला वर्ष को सम्मानित करने के लिए 'मैक्सिको सिटी' में प्रथम 'जागतिक महिला परिषद्' का आयोजन किया गया, इसमें भारत भी सम्मिलित हुआ था। इसके बाद 1980 में कोपनहेगन में, 1985 में नैरोबी में तथा 1995 में बीजिंग में जागतिक महिला परिषदों का आयोजन हुआ। इन चार महिला परिषदों के साथ बीच-बीच में तथा 1995 में बीजिंग के बाद हर पाँच साल में छोटी-छोटी परिषदें होती गयीं जिनमें महिलाओं के विभिन्न विषयों पर चिन्तन, चर्चा, अध्ययन चले। इनमें सम्मिलित सभी देशों में इन परिषदों में जो निर्णय लिये गये, उनके अनुसार विविध कार्यक्रम चले, योजनाएँ बनीं।

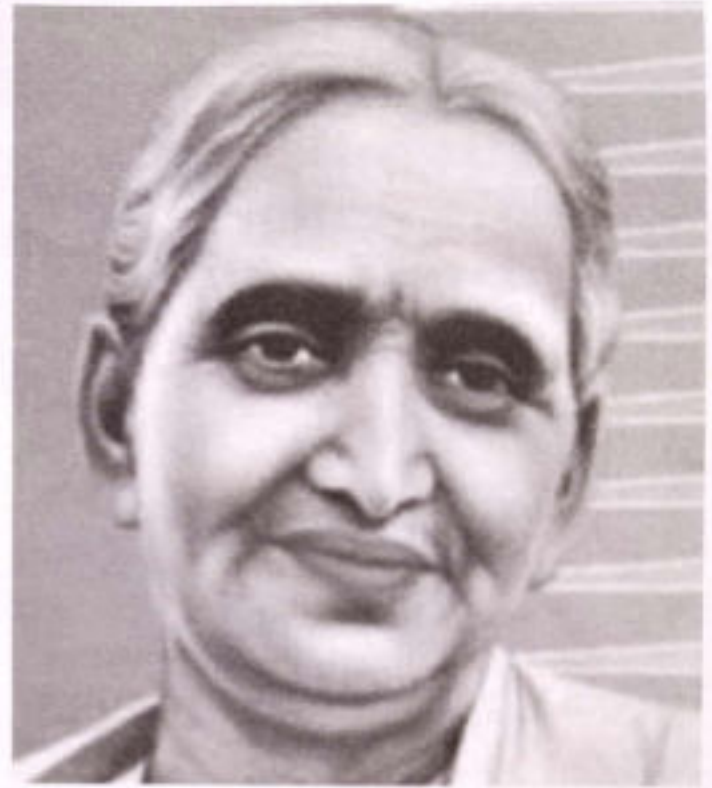
सन् 1980 में भारत में 'राष्ट्रीय महिला दिवस' की स्थापना की गयी। 1977-80 में जो दहेज-विरोधी आंदोलन चले, इसके परिणामस्वरूप 1983-86 के दौरान इनके कानूनों में संशोधन हुए। 1978 में हैदराबाद में हमीजाबी, 1980 में मथुरा-बलात्कार की बहुत चर्चा हुई, उसको लेकर हर स्थान पर आंदोलन चले, परिणामतः 1983 में बलात्कार के संबंध में

क़ानून बना। 1986-87 को दौरान कर्नाटक में 'स्वयं सहायता समूह' की स्थापना हुई और पूरे भारत में इसका फैलाव होने लगा। आज 'स्वयं सहायता समूह' के माध्यमों से न केवल महिला अपितु परिवार सशक्त तथा आत्मनिर्भर होते दिखाई दे रहे हैं।

सन् 1993 में देश में संविधान में संशोधन होकर महिलाओं को स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ जो आगे चलकर 50 प्रतिशत हुआ। इससे महिलाएँ बड़ी संख्या में विविध स्थानों पर काम करने में जुट गईं, उनका निर्णय-प्रक्रिया में सीधा सहभाग बनने लगा, परिणामस्वरूप कई विकास के अछूते मुद्दे आज प्रमुखता से सामने आए हैं। 1992 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' तथा बाद में 'राज्य महिला आयोग' स्थापित हुए जिसके कारण महिलाओं को अपनी मांगें रखने के लिए प्लेटफॉर्म मिला। इसके तहत महिलाओं की समस्याओं के बारे में कई अध्ययन होते गये और उनके आधार पर महिलाओं के लिए कौन-से कार्यक्रम किस प्रकार चलने चाहिये, इसके बारे में शासन को मार्गदर्शन मिलता था।

सन् 2001 में 'राष्ट्रीय महिला नीति' बनी, इसमें भारतीय महिलाओं की स्थिति का जायजा लिया गया तथा उनके लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोज़गार के साथ 'महिला-सुरक्षा' विषय भी गंभीरता से लिया गया और उसके लिए विविध कार्यक्रम, क़ानून बनाए गये। इसमें 'घरेलु हिंसाचार' तथा 'काम के स्थान पर लैंगिक अत्याचार' के विरोध में क़ानून बने। दिल्ली में निर्भया-कांड के बाद बलात्कार-विषयक क़ानून में संशोधन हुए, इनमें आहत महिलाओं को मदद का प्रावधान बना, एसिड हमले को भी गंभीरता से लिया गया और उनमें प्रताड़ित महिलाओं के लिए प्रावधान किये गये।

शिक्षा के क्षेत्र में महिला-शिक्षा को लेकर काफ़ी काम हुआ है। 1851 में जब महात्मा ज्योतिबा फुले तथा सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पाठशाला खोली, उस समय की महिला-शिक्षा की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन-आसमान का अन्तर है। यह लगातार इस दिशा में किए गए प्रयासों का नतीजा है। 1961 में महर्षि धोण्डो केशव कर्वे ने पहला महिला विश्वविद्यालय शुरू किया। आज कई सारे महिला विश्वविद्यालय हम भारत के विभिन्न स्थान पर चलते हुए देखते हैं। लड़कियों के अलग विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के साथ सह-शिक्षा में भी प्रतिशत बढ़ा है। देश को जब स्वातन्त्र्य प्राप्त



हुआ, तब लड़कियों को शिक्षा में प्रमाण 0.69 प्रतिशत था जो आज 60 प्रतिशत के करीब है। सभी प्रकार की उच्च शिक्षा में, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में भी उनका प्रमाण तथा सहभाग सराहनीय है। सॉफ्टवेयर-क्षेत्र, जो नॉल्लेज इण्डस्ट्री कहा जाता है, में भी उनका प्रमाण लगातार बढ़ रहा है। 2004 में जहाँ पुरुषों का प्रमाण इसमें 76 प्रतिशत था महिलाएँ 24 प्रतिशत थीं, 2007 में पुरुषों का 65 प्रतिशत तथा महिलाएँ 35 प्रतिशत हुईं, वहीं आज वह 50 प्रतिशत से भी अधिक दिखाई देती हैं। विज्ञान, तंत्रविज्ञान, संशोधन के क्षेत्र में महिलाएँ काफ़ी आगे आ रही हैं।

महिलाओं की प्रगति का यह चित्र मानव-मन को आनन्द देनेवाला है। साथ ही महिलाओं के सामने अनेक चुनौतियाँ भी हैं, अनेकविध समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। 'जागतिक महिला दिवस' के उपलक्ष्य में इनको देखना, परखना तथा उनको सुलझाने के लिए सही मार्ग खोजना आवश्यक है। महिलाओं का हर क्षेत्र के योग्य तथा उचित सहभाग से ही देश के हर क्षेत्र का विकास संभव है। यह विकास सबके साथ तथा सबके सहभाग से साथ ही सभी के विकास को सामने रखकर करने से सही अर्थ में देश का विकास होगा।

(लेखिका भारतीय स्त्री शक्ति की
राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं)



अभावपि ने बुलंद किया राष्ट्रवादी शक्तियों का हौसला : रघुवर दास

राँची, झारखंड में संपन्न हुआ छात्र-नेता सम्मान समारोह

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् कार्यकर्ताओं ने सदैव देशविरोधी शक्तियों को मुँहतोड़ उत्तर देते हुए राष्ट्रवादी शक्तियों का हौसला बुलंद किया है। इसी का परिणाम है कि देशविरोधी नारा लगानेवाले छात्र-संगठनों को हराकर अभावपि के सदस्य विजयी हुए हैं। उक्त बातें आड़े हाउस, राँची (झारखण्ड) में आयोजित अभावपि के नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों के अभिनन्दन समारोह में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहीं।

श्री रघुवर दास ने कहा कि हमारा लक्ष्य दबे, कुचले, पीड़ित और वंचितों को न्याय दिलाना है। हमें इस लक्ष्य से नहीं भटकना है। छात्रों को कभी भी सस्ती लोकप्रियता के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, यह लोगों को आत्ममुग्ध बना देती है। यह आपको प्रसिद्ध बना सकती है, लेकिन लक्ष्य से भटका देती है। राँची विश्वविद्यालय को देश के श्रेष्ठ 10 विश्वविद्यालय में शामिल करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर ने कहा कि झारखण्ड में अभावपि की जीत संगठन के विचारों की जीत है। संगठन के इन विचारों को अधिक-से-अधिक छात्रों तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि देश को विश्वगुरु बनाने हेतु राष्ट्रवादी विचारधारा अपनाने की आवश्यकता है। जाति-धर्म से ऊपर उठकर कार्य करना, युवा तरुणाई का ध्येय होना चाहिए। भारत पूर्व में दूसरे देशों को देखकर कार्य करता था, परंतु युवाओं के प्रयास के कारण ही आज विश्व के अग्रणी देशों में भारत को तीसरे स्थान पर गिना जाता है।

इस अवसर पर अभावपि के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री के.एन. रघुनंदन ने 'छात्र संघ : हमारा दायित्व, हमारी भूमिका' विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि कि जो छात्र जीतकर आए हैं, उन्हें अधिकार नहीं अपितु दायित्व मिला है, छात्र संघ छात्रों को

प्रतिनिधित्व देता है। इसलिए आप सभी को शिक्षा क्षेत्र में छात्रहित पर प्रयास करना चाहिए। हमें ग्रीन कैम्पस-क्लीन कैम्पस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी युवा तरुणाई को ध्यान देने की आवश्यकता है।

राँची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय ने छात्रों को संकल्प दिलाया कि देश के बाहर व भीतर बिखराववादी तंत्रों का विरोध करेंगे। हम अपनी अखण्डता बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि कामयाबी के लिए आवश्यक है कि मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया जाए। उन्होंने कहा कि अभावपि हर समय परिसर में जायज मांगों को लेकर सक्रिय रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभावपि हमारे साथ मिल-जुलकर कार्य करे।

अभावपि, झारखंड के प्रांत संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि छात्र संघ, छात्रों की आवाज बनकर छात्रहित में कार्य करने का माध्यम है। इस वर्ष जो चुनाव हुआ है, उसमें जीते हुए प्रतिनिधि राज्यभर के छात्रों की आवाज बनकर उभरेंगे। अब विश्राम का समय नहीं है। अब परिसर में छात्रसंघ पदाधिकारी को छात्रहित में कार्य करने की आवश्यकता है। श्री शुक्ल ने राज्य सरकार को अभावपि द्वारा दिए गए सुझाव को बजट में शामिल करने हेतु धन्यवाद दिया है।

इस अवसर पर राँची की महापौर आशा लकड़ा, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड के कुलपति नन्दकुमार इंदु, अभावपि क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह, प्रदेश मंत्री गुंजन मरांडी, राँची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय तथा नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय छात्रसंघ के छात्रनेता सहित अभावपि पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे।

शिक्षा-परिवर्तन

हमारी अवधारणा

प्रा. मिलिन्द मराठे

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होनी चाहिये ? स्वामी विवेकानन्द ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है और हम व्यक्ति विकास और राष्ट्रनिर्माण के लिए शिक्षा चाहते हैं। वस्तुतः शिक्षा-परिवर्तन की अवधारणा का प्रारंभ-बिंदु स्वामी जी की ये दो उक्तियाँ हैं।

दुनिया में हर देश की अपनी विचारधारा रहती है, अपना दर्शन रहता है। जीवन-मूल्य रहते हैं, पद्धतियाँ रहती हैं। उन्हीं को उस देश की विशेषता कहते हैं। इस नाते से राष्ट्र की शिक्षा उस राष्ट्र की आत्मा के अनुकूल होनी चाहिए। मगर भारत की एक समस्या है। हमारा राष्ट्रीय जीवन बहुत पुराना होने के बावजूद भी राष्ट्रीय शिक्षा, हमारे राष्ट्र की आत्मा के बारे में स्पष्टता नहीं है। हमारे हजारों साल के संघर्ष और गुलामी इसका मूल कारण है। उसमें भी ब्रिटिशों की गुलामी से भारत की राष्ट्रीय शिक्षा का क्षरण हुआ। ब्रिटिश शिक्षाविदों में एक मैकाले और दूसरा मैक्समूलर का उदाहरण पर्याप्त है :

"Indian in blood & colour but English in tastes, in opinion, in intellect and in moral." sense of adoration for everything British & contempt for everything Bharatiya.

"India has been conquered once, but she should be conquered again & second conquest should be through education. - Max Muller

और हमने देखा की चीजें बदलीं, रुचि, भाषा, वेशभूषा,

अवधारणाएँ बदलीं, नजरिया बदला। अपने ही जीवन-मूल्यों को बारे में भ्रांतियाँ खड़ी हुईं। प्रो. दौलत सिंह कोगरी जी के स्पष्ट वादों में कहा हुआ है कि जो यूरोप-केन्द्रित हुआ है उसे भारत-केन्द्रित करना है।

हमारी राष्ट्रीयता की विशेषता क्या है ? आधारभूत बातें क्या हैं ?

- सर्वत्र एक ही तत्त्व विराजमान है। एक ही तत्त्व अनेक हो गया।
- Manifestation oneness in different. Not unity in diversity. अतः संघर्ष नहीं समन्वय, स्पर्धा नहीं सहयोग, परस्पर अवलंबिता, अनिश्चितता, सहयोग की दृष्टि। उसको मान्यता संघर्ष होंगे, परंतु वह आधार नहीं बनेगा। आधार सहयोग। भाषा अनेक भाव एक।
- समाज बदलेगा, वेशभूषा बदलेगी, परिस्थितियाँ बदलेगी, गाँवों-नगरों की रचना बदलेगी। लेकिन मूल धारणा नहीं बदलेगी। व्यवस्था अनेक, धारणा एक।
- यदि विश्व का मंगल होना है, तो समझना पड़ेगा कि मैं दुनिया



का मालिक नहीं हैं। दुनिया के संसाधनों पर सबका अधिकार है, अतः त्यागपूर्वक उपभोग करे।

क्या हमारी शिक्षा उपर्युक्त राष्ट्रीय आत्मा से संबंध स्थापित कर सकेगी? क्या भारत में शिक्षा भारतीय होगी?

1. 1773 में भारतीय शिक्षा के यूरोपीयकरण का प्रारंभ। 1781 में प्रथम महाविद्यालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। 1813 में India Education Act. 1835 में मैकाले शिक्षानीति, 1857 में बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना से भारत में ब्रिटिश शिक्षा दृढ़मूल हुई। दो-तीन पीढ़ियाँ उसमें शिक्षित हुई। उसके बाद 1866 में श्रीअरविंद के नाना राजनारायण बसु द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रथम प्रयास। "Society for promotion of National feeling Among the Educated Native of Bengal." की स्थापना। उसके बाद गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शान्ति निकेतन, श्रीनिकेतन एवं विश्वभारती का प्रयोग। श्रीअरविन्द, विवेकानन्द एवं भगिनी निवेदिता, स्वामी दयानन्द सरस्वती एवं स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती द्वारा दयानन्द एंग्लो वेदिक स्कूल की शृंखला एवं गुरुकुलों का प्रयोग अंत में महात्मा गाँधी जी के वर्धा योजना नाम के प्रयोग चले।
2. राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयासों को शासन का विरोध रहा।

3. राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयोग करनेवाले स्वयं ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में पढ़े थे। अतः उस शिक्षा को पूर्णतः नकारना असंभव था। अतः वे पूर्व-पश्चिम के समन्वय-जैसी बात करते रहे। आज यह बाद और कठिन है, इस शिक्षा में पढ़ते अब 10 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं।

1. क्या शासन की मान्यता अनिवार्य है?

शिक्षा-तंत्र की स्वायत्ता और आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्ण है। शिक्षातंत्र के तीन पक्ष हैं : शैक्षिक, आर्थिक और प्रशासनिक। आज शैक्षिक पक्ष राज्य एवं केन्द्र, आर्थिक पक्ष यूजीसी और प्रशासनिक पक्ष शासन ही देखता है। वास्तव में शिक्षा सत्ता और अर्थ के अधीन न होकर धर्म के अधीन होनी चाहिए। शिक्षा को धर्म से विमुख कर सत्ता और अर्थ के दायरे में लाने की पद्धति ब्रिटिश की है। क्योंकि उन्हें व्यापार-सत्ता-शिक्षा आवश्यक थी। शिक्षा सत्ता चलाने के लिए और सत्ता अनिर्बंध व्यापार करने के लिए चाहिये थी। आज शिक्षा में शासन की मान्यता अनिवार्य बन गयी है।

2. क्या शिक्षा का लक्ष्य मात्र अर्थार्जन है?

आज धर्म सभी व्यवहारों का अधिष्ठान नहीं रहा। अर्थ और काम को धर्म के अधीन नहीं रखा गया। आज

लौकिक व्यवहार में धर्म कम हो गया। मोक्ष कल्पना ही समाप्त हुई। काम जीवन का लक्ष्य बना और अर्थ कामपूरति का अनिवार्य साधन। अतः अर्थप्राप्ति की क्षमता ही शिक्षा का उद्देश्य बन गया। और जिससे अर्थार्जन की क्षमता नहीं बढ़ती, उस शिक्षा की जरूरत क्या है? यह भाव आ गया।

3. छात्र एवं अध्यापक का जीवमान संबंध परोक्ष हुआ : अतः वर्तमान शिक्षा के परिवर्तन हेतु हमारी अवधारणा, Our thought process क्या होनी चाहिये?
4. शासन की मान्यता से अधिक समाज की मान्यता एवं विद्वानों की मान्यता आवश्यक है।

भारतीय परंपरा में शिक्षा हमेशा स्वायत्त रही है। शिक्षा कभी भी शासन का विषय नहीं रहा। शासन उसको समर्थन दे सकता है, संरक्षण दे सकता है, सहायक बन सकता है, लेकिन नियंत्रक बनना ठीक नहीं है।

समाज की मान्यता : समाज को लगना चाहिये यह उपयुक्त है, लाभदायक है तो वह समर्थन देगा, सहायता देगा। संरक्षण देगा।

विद्वानों की मान्यता : ज्ञान में गुणवत्ता, उत्कृष्टता, शुद्धता चाहिये। यह तो तब ही दे सकते हैं।

अतः -

- 1-1 स्वायत्त राष्ट्रीय शिक्षा पीठ की स्थापना (National Education Commission)
- 1-2 स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा का एकात्मिक विचार, दिशा-निर्देश एवं क्रियान्विति हो। उच्च शिक्षा की सभी संकायें एक छत के नीचे आयें, जैसे- कृषि-शिक्षा, वैद्यक शिक्षा, विधि-शिक्षा आदि।
- 1-3 राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (NACC) और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) द्वारा की जानेवाली गुणवत्ता का प्रमाणीकरण भारतीय मानकों एवं परिस्थितियों के अनुकूल संकेतकों के आधार पर स्वयं की रैंकिंग पद्धति से करना अनिवार्य हो। गुणवत्ता का परीक्षण एवं मान्यता केवल विद्वान् करें। अतः निजी संस्थाओं को प्रत्यायन एजेंसी न बनाया जाय।
2. झूठ भारतीय अधिष्ठान के रूप में, मानकों के रूप में मापदण्डों के रूप में शिक्षा की ज्ञानधारा चले। वैधिकता के संदर्भ में जो अच्छा है, कल्याणकारी है, वह पूरे विश्व से हम स्वीकार करेंगे, लेकिन भारतीयता के रूप में परिवर्तित

करके उसको अपनायेंगे। अतः

- 2-1 शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिले। प्राथमिक से लेकर अनुसंधान तक के पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में चलाये जाये। उपलब्ध रहे। (for eg. spoken tutorial project in IITM allows learning of software in all Indian language.)
- 2-2 भारतीय भाषाओं में सभी प्रकार का ज्ञान देने का प्रयोग केन्द्र सरकार देश भर में कुछ विश्वविद्यालय शुरू करके चलाये।
- 2-3 संस्कृत-भाषा, यह प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं विज्ञान का कोश है। वह अन्य सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी है। अतः संस्कृत अध्ययन-अध्यापन को बढ़ावा देना।
- 2-4 भारत के अतीत के बारे में गौरव का आत्मसम्मान का भाव छात्रों में जगना आवश्यक है अतः भारतीय वैज्ञानिक, ऋषि, विद्वानों का जागतिक स्तर पर योगदान क्या है, यह पाठ्यक्रम के माध्यम से बताना।
- 2-5 पाठ्यक्रम, माहोल और व्यवस्थापन में भारतीयता का आग्रह भारतीय ज्ञान-विज्ञान की परम्परा के साथ भाव जागरण एवं सह-संवेदना का अंतर्भाव। आध्यत्मिकता का अनुभव। Spiritual Knowledge आवश्यक है, क्योंकि इससे चरित्र बनता है। spiritual यानि धर्म का शिक्षण। शिक्षित व्यक्ति कैसा होता है?
वह सृष्टि का प्रयोजन समझता है। सर्वजनहित की दृष्टि से विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। जिसके मन एवं इंद्रिय उसके वश में रहते हैं, शरीर स्वस्थ होता है। वह व्यक्ति साक्षर के साथ-साथ सज्जन एवं चरित्रवान् होता है। उस पर समाज भरोसा कर सकता है, भारत में विद्वत्ता और चारित्र्य एकसाथ होने की अपेक्षा की है। भारतीय शिक्षा के दर्शन को संत कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं—
**पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय।
ढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय ॥**
प्रेम - समाज के प्रति, सृष्टि के प्रति, सजीव निर्जीव के प्रति
अतः धर्म शिक्षण आवश्यक है।
**धृति क्षमादमस्तेयशौचमिन्द्रिय निग्रहः।
धीर्विद्योसत्यमक्रोधो दशकम् धर्मलक्षणम् ॥**
ये धर्म के दस लक्षण हैं।
- 2-6 छात्रों को अपने परिवेश से जोड़ना। समाज का दर्शन

कराना। समाज से शिक्षा को जोड़ना। प्रत्येक स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्र को पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही न्यूनतम तीन माह की सामाजिक अनुभूति देना जिससे वह सीख सके।

"In the vacation one weel for Nation. After Education one Year for Nation"

3. भारतीय परंपरा में विद्या, अन्न और औषधि कभी भी क्रय-विक्रय के पदार्थ नहीं रहे। अर्थ के संदर्भ में कभी उसका मूल्य आंका नहीं गया। इसलिए विद्यार्थी के लिए सारी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था समाज आधारित होगी।

3-1 सरकार को उदार मानसिकता एवं सामाजिक दायित्व से सकल घरेलु उत्पाद का न्यूनतम 6 प्रतिशत या बजट परिव्यय का 90 प्रतिशत खर्च करना चाहिये और धीरे-धीरे इस व्यय को बढ़ाना चाहिये। इससे शिक्षा का बाजारीकरण बंद होगा और शिक्षा, सुलभ और सभी को मिलेगी।

3-2 ई.डी.बी.आई. की स्थापना हो और उसके द्वारा कई वित्तीय गतिविधियाँ, जैसे- गरीब एवं मेधावी छात्रों हेतु व्याजमुक्त ऋण, शिक्षावृत्ति, अनुसंधान हेतु राशि करें जिससे पैसे के अभाव में कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे।

3-3 शिक्षा हेतु दान की पद्धति समाज में प्रोत्साहित हो। आयकर छूट-जैसे उपाय हों। अभिभावक, समाज के धनदाता, पूर्व छात्रों से दान ले सकते हैं।

4. परिवार-शिक्षा, यानि परिवार की शिक्षा और परिवार में शिक्षा। प्रत्येक बालक के प्रथम गुरु माता एवं पिता होते हैं। व्यक्ति के जीवन विकास का 66 प्रतिशत हिस्सा, समय परिवार में व्यतीत होता है। भारतीय चिन्तन में समाज की मूल इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। परिवार में गृहस्थाश्रम होता है। अतिथि-स्वागत, यज्ञ, दान होते हैं। इससे शिक्षा मिलती है। परिवार-प्रबोधन की आवश्यकता।

5. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार है अच्छा शिक्षक : शिक्षक-सम्मान, शिक्षकों को गरिमा रखना आवश्यक है। शिक्षक-शिक्षा ठीक हो। शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण।

6. संगठन से शिक्षा : संगठन संस्था से भिन्न होता है। उसमें वैधानिक नियम नहीं होते। संगठन को सदस्यों में नियमों का स्वेच्छ से पालन करने की वृत्ति होती है। क्रियान्वयन में प्रमाणिकता का विश्वास होता है। इस प्रकार के संगठन की शक्ति का मूल स्रोत होता है त्याग, तपस्या, अभीनिवेश-शून्यता और निःस्वार्थ रूप से किया शुद्ध सात्त्विक प्रेम। शिक्षा के किसी भी स्तर पर छात्रों को ऐसे संगठन से जोड़ना। इस प्रकार का जीवन जीनेवाले व्यक्तियों का सान्निध्य ही शिक्षा प्रदान करता है, संस्कार देता है। आत्मिक समाधान, सेवा की भावना देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, रामकृष्ण मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग आदि संगठन ऐसे कई उदाहरण आते हैं। गैरसरकारी संगठनों में अनुभव लेना। इण्टर्नशिप करना, सामाजिक कार्य करना, यह संगठन से शिक्षा का उदाहरण है।

7. सह पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ द्वारा शिक्षा : छात्रों के व्यक्तित्व-विकास हेतु खेलकूद, संगीत, नाट्य, नृत्य, चित्रकला, वादन, योग, व्याख्यान द्वारा शिक्षा। विविध उपक्रमों के द्वारा अनुभवजन्य शिक्षा होनी चाहिए जिसे हम अनुभव से सीखना कहते हैं। पर्यावरण-संरक्षण, ऊर्जा-बचत के प्रयास, वृक्षारोपण, साक्षरता अभियान-जैसे उपक्रमों के द्वारा शिक्षा।

8. जीवनार शिक्षा ग्रहण करने की शिक्षा भी अनिवार्य Learnig how to learn for Lifelong period स्वामी विवेकानन्द की दो उक्तियाँ :

1. शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है (Education is the manifestation of the perfection already in man) और
2. हम व्यक्ति विकास और राष्ट्रनिर्माण के लिए शिक्षा चाहते हैं। (We need manmaking and nation building education)

शिक्षा-परिवर्तन की हमारी अवधारणा का प्रारंभ-विंदु स्वामी जी की ऊपर निर्देशित दो उक्तियाँ हैं।

(लेखक अभावित के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

आठ मार्च को विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहले की अपेक्षा वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन यह काफी नहीं है। इस उपलक्ष्य पर महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, स्वावलम्बन, समानता आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख ममता यादव से 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' - संवाददाता अजीत कुमार सिंह ने बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश...



सशक्त महिला-सशक्त राष्ट्र का आधार है : ममता यादव

■ महिला-सशक्तिकरण की दिशा में अभावों के क्या प्रयास हैं ?
सशक्त महिला-सशक्त समाज व राष्ट्र का आधार है। यह भाव अभावों का हमेशा से ही रहा है। अतः अपने गठन के समय से ही छात्र-छात्राओं की समान भागीदारी संगठन कार्य में हो, ऐसा अभावों के संविधान में वर्णित है और यह मात्र लिखने के लिए नहीं है। हमने व्यावहारिक रूप में इसे करके दिखाया है।
महिला सशक्तिकरण, हमारे लिए एक नारा नहीं है, अपितु अभावों की लगभग 5,000 इकाइयों में वर्ष के

365 दिन होने वाली सभी गतिविधियों में छात्राओं का सहभाग छात्रों जितना ही होता है, जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारे लिए सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। अभावों का अधिवेशन हो या सम्मेलन, सेमिनार हो या कार्यशाला, स्वच्छता-अभियान हो या रक्तदान-शिविर, आंदोलन हो या सर्वेक्षण, अनुभूति सभी में छात्राओं की समान सहभागिता और नेतृत्व उनके सशक्तिकरण का परिचायक है।

■ आप स्वयं एक शिक्षिका हैं, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की

शैक्षणिक स्थिति पर आपकी क्या राय है ?

मैं एक शिक्षिका हूँ, साथ ही शिक्षा-क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठन की कार्यकर्ता भी हूँ। देशभर में प्रवास करते हुए जब शिक्षा-क्षेत्र में महिलाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करती हूँ, तो लगता है कि आज महिलाएँ शिक्षा-क्षेत्र में नित्य नयी प्रतिभा गढ़ रही हैं। वे निरंतर आगे बढ़ रही हैं। जब 10वीं, 12वीं, स्नातक, परास्नातक का परीक्षा-परिणाम आता है तो समाचार-पत्र छात्राओं की कामयाबी की कहानियों से भरे रहते हैं। अधिकांश टॉपर छात्राएँ ही रहती हैं। मेडिकल, एलएल.बी., इंजीनियरिंग, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी बड़ी संख्या में छात्राएँ कामयाब हो रही हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। परंतु एक दूसरा पहलू भी है, यदि हम आँकड़ों की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 में साक्षरता-दर, पुरुष का 76.8 प्रतिशत तथा महिला का 50.28 प्रतिशत रहा। यह चिन्ताजनक है। अतः शिक्षा की ओर अभी और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

■ अभावपिप में वर्तमान छात्रा कार्य की स्थिति से क्या आप संतुष्ट हैं ?

देखिये, संतुष्टि तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक, एक-एक छात्रा शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, रोजगार, स्वावलम्बन, सुरक्षा और स्वाभिमान के साथ समाज में सिर ऊँचा उठाकर अपना योगदान राष्ट्र-पुनर्निर्माण में देते हुए स्वयं को सशक्त नहीं महसूस करने लगेगी। लेकिन एक अर्थ में, मैं आज की परिस्थिति में अभावपिप में छात्राओं की सहभागिता से संतुष्ट हूँ। हमारा कार्य लगातार बढ़ रहा है। आज सभी क्षेत्रों में छात्राएँ हमारे साथ काम में आ रही हैं। अपने परिसर में नेतृत्व दे रही हैं। आज हमारी सदस्यता में भी लगभग 32 प्रतिशत छात्रा-कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रही हैं।

■ छात्राओं में नेतृत्व-क्षमता बढ़ाने हेतु अभावपिप क्या प्रयास कर रही है ? वर्तमान में प्रांत-स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अभावपिप में कोई छात्रा-कार्यकर्ता है ?

अपनी योग्यता के आधार पर छात्राएँ स्वयं विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। इकाई-स्तर पर मंत्री, सह मंत्री, जिला प्रमुख, जिला-संयोजक, समय-समय पर अनेक प्रांतों की प्रदेश मंत्री, वर्तमान में भी हिमाचल व जम्मू और

कश्मीर की प्रदेश मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व छात्राएँ बखूबी निभा रही हैं। इसके साथ ही नगर-अध्यक्ष, प्रदेश-अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका में प्राध्यापिकाएँ हैं। हमारे विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य भी छात्राएँ पूरे मनोयोग से कर रही हैं चाहे वह विश्व विद्यार्थी युवा संघ हो या विकासार्थ विद्यार्थी।

■ अभावपिप द्वारा किया गया, कोई ऐसा आंदोलन, जो छात्राओं द्वारा नेतृत्व किया गया हो, बतायें।

ऐसे आंदोलनों की संख्या बताना मेरे लिए कठिन होगा। क्योंकि अभावपिप का ऐसा कोई आंदोलन नहीं होगा जिसमें छात्राओं ने नेतृत्व न किया हो या उनका सहभाग न रहा हो। चाहे वह 1990 का आतंकवाद के विरुद्ध 'चलो काश्मीर' आंदोलन हो, 2002 का 'शिक्षा और रोजगार' हेतु दिल्ली कूच हो या 2008 का बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध 'चलो चिकन नेक' का आंदोलन हो, छात्राओं ने निर्भीकता से ऐसे सभी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। जब 2012 में दिल्ली में निर्भया-काण्ड हुआ, उसकी आवाज़ उठानेवाले भी सबसे पहले अभावपिप-कार्यकर्ता ही थे। पानी की बौछार और अन्य अनेक प्रताड़नाओं के बावजूद छात्र और छात्राएँ पीछे नहीं हटी थीं।

■ भारतीय संस्कृति में महिलाओं को विशिष्ट स्थान दिया गया है लेकिन महिलाओं को आए दिन भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जबकि संविधान में इसके खिलाफ कठोर क़ानून का प्रावधान भी है ? इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए ?

भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को अति विशिष्ट स्थान दिया गया है। वेदों में लिखित है— स्त्रियाः पन्थाः देवा अर्थात् स्त्री निकल रही हो तो राजा को भी मार्ग देना चाहिये। स्त्री-सम्मान के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे वेद, पुराणों, ग्रंथों में। परंतु वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो जैसा आपने कहा कि कठोर क़ानूनों के बावजूद भी स्त्रियों के प्रति भेदभाव व अत्याचार समाप्त नहीं हो रहे तो मेरी दृष्टि में इसका एकमात्र समाधान है, हमें स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हम न इसे देवी मानें न दासी, बस मानवी मान लेंगे तो भी वह भेदभाव मुक्त हो जायेगी। देखिये, क़ानून अपना काम करता है, यह एक पहलू है।

परंतु जब तक महिला को एक मनुष्य के रूप में सम्मान नहीं देंगे यह समस्या समाप्त नहीं हो सकती।

- पुरुषों की तुलना में देश में महिलाओं का लिंगानुपात कम है, इसमें सुधार के लिए अभाविप के क्या विचार हैं ?

देखिये जब भी लिंगानुपात की बात आती है तो यह प्रश्न मुझे अत्यंत विचलित कर देता है। जब 2011 की जनगणना-रिपोर्ट आई तो देश में सर्वाधिक कम 0-6 आयु वर्ग की लड़कियों का राज्य हरियाणा वर्णित था। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह पीड़ादायक जानकारी थी क्योंकि मैं भी हरियाणा राज्य से आती हूँ। लेकिन इसके बाद सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों में वृद्धि हुई है। अभाविप में तो अनेक वर्षों से 'महिला-सुरक्षा', 'कन्या- भ्रूण हत्या'-जैसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध अनेक सेमीनार, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। अनेक आंदोलन भी किए गए हैं। जनजागरण-अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मेरा मत है कि इस समस्या का निदान संभव है— 1. बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, यह विश्वास बहाल हो, 2. दहेज नहीं देना पड़ेगा, यह सुनिश्चित हो जाये। आप विश्वास कीजिये माता-पिता के लिये बेटी कभी भी बोझ नहीं होती। हाँ, इसमें सरकार व समाज— दोनों का योगदान जरूरी है। हमें उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे, बिहार के धरहरा ग्राम की तरह जहाँ बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाए जाते हैं। हरियाणा के कुछ ग्रामों में अब बेटी पैदा होने पर कुआँ-पूजन किया जाता है। उत्सव होते हैं। ये छोटे-छोटे प्रयास हैं, परंतु इनके परिणाम उत्साहवर्धक और दूरगामी होंगे, इसमें संदेह नहीं है।

- अभाविप में छात्रा-कार्य हेतु आगामी योजनाएँ क्या हैं ?

अभाविप में छात्रा-कार्य यह एक नियमित चलनेवाला कार्य है। हमारे यहाँ छात्र-छात्राएँ मिलकर सभी गतिविधियों में भाग लेते हैं। फिर भी कुछ कार्यक्रम अलग से भी किए जाते हैं। गत दो वर्षों से हम सभी प्रांतों में छात्राओं की बड़ी संख्या के साथ दो दिन के सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं जिसमें अनेक विषयों पर चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तावों को पारित करना, परिसर-कार्य, आदि विषयों पर छात्राएँ अपने

विचारों की प्रस्तुति देती हैं। इससे उनमें नेतृत्व-क्षमता का विकास होता है। इस वर्ष भी अभी तक चार प्रांतों के सम्मेलन हो चुके हैं, बाकी में होने हैं।

- ग्रीष्माकालीन अवकाश में व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन इकाई स्तर किया जायेगा।

- 'उच्च शिक्षा में छात्राओं की स्थिति' विषय पर पूरे देशभर में एक सर्वेक्षण इस वर्ष हम करनेवाले हैं जिसका प्रारंभिक कार्य पूर्ण हो गया है। अगले सत्र के प्रारंभ में इस सर्वेक्षण को हम पूरा करेंगे, ऐसा लक्ष्य है। इसमें सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तक पहुँचने का प्रयास हम करेंगे। इसकी रिपोर्ट के अनुसार पर उच्च शिक्षा में क्या बदलाव लाने चाहिये, ऐसे सुझाव हम संबंधित विभाग को देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा यह सर्वेक्षण उच्च शिक्षा में छात्राओं आकलन पर पायेगा और उनकी समस्याओं, कठिनाइयों के समाधान की दिशा में हम अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे पायेंगे।

प्रिय मित्रो !

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का फरवरी, 2017 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह अंक गणतंत्र दिवस, महिला दिवस के विभिन्न विषयों के साथ-साथ विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए है। आशा है, यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें :

संपादक, 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'

'छात्रशक्ति भवन', 26 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली-110002.

फोन : 011-23216298

वेबसाइट : www.abvp.org

✉ chhatrashakti.abvp@gmail.com

📘 www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti

🐦 www.twitter.com/chhatrashakti1

देशभर में मनाई गई नेताजी सुभाष जयन्ती

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, भोपाल (मध्य भारत) के तत्त्वावधान में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 120वीं जयन्ती धूमधाम से मनाई गयी। कार्यक्रम में भोपाल-स्थित मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य वी.के. श्रीवास्तव ने कहा कि नेताजी आज के युवाओं के प्रेरणास्रोत हैं। आज के युवा जहाँ अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं, ऊँचे पद के लालयित हैं, वहीं नेताजी ने भारतभूमि को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए अपनी आईसीएस (अब के आईएएस) के पद को तुकरा दिया था। नेताजी ने आईसीएस की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। घरवालों के मना करने के बावजूद देश की स्वतंत्रता में कूद पड़े। वर्तमान समय में नेताजी-जैसे युवाओं की देश को जरूरत है। अभाविप के महानगर मंत्री अजय पाटीदार ने कहा कि नेताजी का जीवन-चरित्र हमें देशसेवा के लिए प्रेरित करता है।

सिलीगुड़ी (प. बंग) में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयन्ती के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर इतिहास में पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की सिलीगुड़ी शाखा की ओर से 120 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गयी। 120 मीटर लंबी भारत की शान को अभाविप के 120 सदस्यों ने पकड़कर मार्च किया। नेताजी जयन्ती के अवसर पर कंचनजंघा स्टेडियम से निकली तिरंगा-यात्रा हिलकर्ट रोड, सेवक रोड के रास्ते विधान रोड होते हुए वापस स्टेडियम पहुँचकर समाप्त हुई।

परिषद् के नगर-सचिव विवेक शर्मा ने बताया कि भारत का स्वतंत्र कराने में नेताजी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वर्तमान युवा वर्ग को नेताजी के जीवनादर्शों का अनुसरण करना चाहिए।

सामाजिक समरसता के प्रतीक थे बाबा साहेब : विनय बिदरे

सामाजिक समरसता पर कर्नाटक के मंगलुरु में कार्यक्रम आयोजित

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समतामूलक समाज के निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब का मानना था कि जब तक समाज में सभी वर्गों के प्रति समरसता का भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। उनके विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। युवाओं को उनके विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र-निर्माण में आगे आना चाहिये। ये बातें अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे ने कहीं। श्री बिदरे अभाविप द्वारा मंगलुरु (कर्नाटक) में आयोजित डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती समारोह पर 'समरसता के साथ राष्ट्रवाद की ओर' विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 1930 नासिक काँग्रेस में डॉ. अम्बेडकर और उनके समर्थकों को नासिक मन्दिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि काँग्रेस बाबा साहेब के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। काँग्रेस की कथनी और करनी में आसमान-जमीन का अन्तर है। बाबा साहेब के नाम पर वर्तमान में कई छात्र-संगठन विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम कर

रहे हैं, लेकिन उनके विचारों का वे लोग कभी अनुसरण नहीं करते। बाबा साहेब को किसी जाति-विशेष में बाँधना घोर अन्याय है क्योंकि वे हमेशा गरीब, वंचित, पीड़ित वर्ग के हितों की संरक्षण की बात करते थे।

इस मौके पर अभाविप के प्रान्त उपाध्यक्ष केशव बंजर ने बताया कि डॉ. अंबेडकर ने समानता की स्थापना के लिए अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह एक महान् समाज सुधारक थे और सामाजिक सुधारों में उनका योगदान अतुलनीय है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉ. साहेब के संदेश को युवाओं तक पहुँचाना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर स्नातकोत्तर अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉ. देवराज कश्मीर ने की। इस मौके पर अभाविप की महानगर अध्यक्ष श्रीमती आशालता व नगर मंत्री जीवनराज सहित अभाविप के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।

बजट में शिक्षा-क्षेत्र और युवाओं की स्थिति

भावी अर्थव्यवस्था की तस्वीर उजागर करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 21.47 लाख करोड़ रुपये का बजट लोकसभा में पेश हुआ। यह राशि पिछले बजट से 1.69 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है। युवा, महिला, किसान, छोटे कारोबारी, वरिष्ठ नागरिक, उद्योग-जगत, आदि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट देश के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने, रोजगार के नये अवसर पैदा करने तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। देश की लगभग आधी जनसंख्या 25 साल से कम उम्र की है। ऐसे में बजट का सर्वाधिक असर इसी वर्ग पर पड़ता है। स्कूली स्तर तक दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता जाँचने के साथ ही छात्रों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उच्च शिक्षा की सभी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बजट में शिक्षा-क्षेत्र के लिए कुल 79,685.95 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसमें से स्कूली शिक्षा (प्राथमिक और सीनियर सेकेंडरी) के लिए 46,356.25 करोड़ रुपये और शेष उच्च शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। दो नये एम्स खोलने के साथ मेडिकल की 5,000 सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। सरकार ने सूचना-प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के लिए 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ 'स्वयं' प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही सीबीएसई की भूमिका केवल शैक्षिक कार्यों तक सीमित हो—ऐसा भी सुनिश्चित हुआ है। कौशल-विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए गाँव के स्तर पर महिला-सशक्तिकरण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय बजट 2017-18 को लेकर, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न युवाओं का नज़रिया जानने के लिए 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के संवाददाता उत्कर्ष श्रीवास्तव ने देशभर के छात्रों से बात की और उनकी राय जानी। प्रस्तुत है वित्तीय बजट 2017-18 पर युवाओं की राय...

देशभर में 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और इनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या लाखों में है। यदि अनुमान लगाया जाए तो अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ छात्रों के ऊपर होनेवाले खर्च और उनको प्रदान की जा रही सुविधाएँ काफी कम हैं। विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त धन न होने की वजह से न तो नये छात्रावास बन रहे हैं और न ही प्रयोगशालाओं की स्थिति में कोई सुधार हो रहा है। आए दिन शोधार्थियों को कोष के लिए इधर-उधर भटकते देखा गया है। समय पर धन और सुविधा न मिलने से उसका प्रभाव शोध-कार्यों पर भी पड़ता है। इस बार बजट में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अलग से 130 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एएमयू आदि परिसर में शोध एवं अध्यापन कार्य कर रहे लोगों के लिए यह बहुत अच्छी बात है। यूजीसी के बजट में भी सुधार की बात कही गई है और साथ ही इसके बजट में 200 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। यह एक अच्छा कदम है।

—संस्कृति खरे

शोध-छात्रा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

शिक्षा में गुणवत्ता की बहुत आवश्यकता है, इस पर विशेष ध्यान देना केंद्र सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाता है, केन्द्रीय विद्यालयों को कम फीस में शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इस बजट में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 505 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। इस बजट का सही प्रयोग बच्चों के हित के लिए किया जाएगा जिससे केन्द्रीय विद्यालय के बच्चे देश-विदेश में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

—रोहित मीणा

एमएड छात्र, राजस्थान विश्वविद्यालय

स्कूली शिक्षा का बजट पिछले साल की तुलना में मात्र एक हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। इस राशि से प्राथमिक शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करना संभव नहीं होगा; क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं और बहुत-से विद्यालयों में पर्याप्त

आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। वहीं प्राथमिक स्तर के लगभग 10 फीसदी विद्यालय एकल शिक्षक विद्यालय हैं। ऐसे में 'शिक्षा का अधिकार' कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए संसाधनों का अभाव बना रहेगा। विद्यालयों में मूल्यांकन के लिए (असेसमेंट प्रोग्राम) के लिए पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जबकि इस बार के बजट में मात्र 67 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

—सुष्मिता पुरकायस्थ

डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन, सिलचर यूनिवर्सिटी, असम

शिक्षा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। प्राइमरी से लेकर पीएच.डी. तक की पढाई महंगी होती जा रही है। निजी मेडिकल कॉलेज 20 से 25 लाख रुपये भेंट लेकर दाखिला देते हैं। बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ प्राइमरी में दाखिले के लिए भी भेंट देनी पड़ता है। आए दिन प्रवेश-परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, आदि की पढाई इतनी महंगी है कि आम आदमी उसे वहन नहीं कर सकता, आखिर इन चीजों की तरफ सरकार का ध्यान कब जायेगा? बजट में इनके लिए प्रावधान कब बनेगा?

—गौरव वद्रे

एम.कॉम. छात्र, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

स्वास्थ्य-शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए परास्नातक (पीजी) की पाँच हजार सीटों की बढ़ोत्तरी की गई है, लेकिन मेडिकल के अन्य क्षेत्रों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्टीमेट्री, बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., रेडियोग्राफी, बी.पी.टी., नर्सिंग, इत्यादि पाठ्यक्रमों की स्थिति आज बहुत बुरी है। इक्के-दुक्के सरकारी कॉलेजों को छोड़कर बाकी जगहों पर यह पाठ्यक्रम उपलब्ध भी नहीं है। केवल सीटें बढ़ाने से मेडिकल शिक्षा में सुधार नहीं होगा। सरकार को मेडिकल कॉलेजों की अन्य जरूरतें, जैसे-आधुनिक उपकरण, शिक्षकों की कमी, छात्रावासों की कमी, आदि चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए था। पैसे देने से कुछ नहीं होगा, पैसे का सही तरह से उपयोग हो— यह देखनेवाली बात है।

—अभिनव मोरे

डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज, पुणे

अन्य देशों की तरह भारत में भी परीक्षाओं के लिए एक पेशेवर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाये। अभी तक यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई, सीबीएसई, विश्वविद्यालय समेत कई एजेंसियाँ हैं, लेकिन एकल माध्यम होने से सभी को लाभ मिलेगा। युवाओं के रोजगार हेतु संकल्प कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में खोले जा रहे 'अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र' की मदद से उन युवाओं को मदद मिलेगी जो देश के बाहर नौकरी करने के इच्छुक हैं। इसलिए यह बजट सकारात्मक है।

—याशिका शर्मा

हिंदी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में जो कदम उठाए हैं, वे बहुत संतोषजनक तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी देश को आगे ले जाने में मददगार सिद्ध होंगे। बजट ट्रेन, स्मार्ट सिटी-संबंधी योजनाएँ इस बार सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं दिखीं। रेलवे ई-टिकट पर सर्विस टैक्स फ्री हो गया है, ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई जा रही है। भारत में नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपये का बजट पारित हुआ है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर की मदद से 150 लाख ग्राम पंचायतों में तेज इंटरनेट पहुँचाया जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत-से क्षेत्रों में बुनियादी सुधार के अपेक्षित उपाय नहीं दिख रहे हैं।

—देवेन्द्र कुमार झा

एम.टेक छात्र, एनआईटी, राउरकेला

दो-दिवसीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यशाला दिल्ली में संपन्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की दो-दिवसीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यशाला का आयोजन दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 28 एवं 29 जनवरी को किया गया। नयी शिक्षा नीति, राष्ट्रवाद, परिषद् की कार्यप्रणाली, वैश्विक स्तर पर भारत का बदलता परिदृश्य, परिषद् की वैचारिक यात्रा, परिषद् की अकादमिक संस्थानों में कार्यप्रणाली, गौरवशाली संस्कृति आदि विषयों को लेकर चर्चा हुई।

कार्यशाला में अपने विचार रखते हुए प्रो. अश्विनी महापात्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह से भारत की छवि का निर्माण हुआ है, उसमें परिषद् का भी अमूल्य योगदान है। क्योंकि परिषद् वह कारखाना है जहाँ पर उत्तम चरित्र का निर्माण होता है।

भारतीय संस्कृति विषय पर बोलते हुए प्रो. रजनीश ने कहा कि भारतीयता एक सनातन यात्रा है, एक अमृत पंथ है जो अनादि से अनंत तक विस्तृत है। भारत की आत्मा या भारतीयता को केवल इतिहास के दिशा-सन्दर्भों में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का इतिहास घटनाओं एवं तथ्यों का पुंज मात्र नहीं है। प्रत्येक घटना एवं काल का इतिहास एक मूल्य-दृष्टि का सर्जन करता है जो देशानुकूल, कालानुकूल, व्यावहारिक परिवर्तनों के साथ ही सत्य के खोज एवं उसकी प्राप्ति के आग्रह से युक्त हो सर्वतोभावेन लोकमंगल के लिए पर्यासरत समष्टि जीवन का मूल्याधिष्ठित स्वरूप प्रस्तुत करता है। भारतीय संस्कृति अत्यंत आशावादी जीवन-पद्धति है एवं इसमें जीवन का उद्देश्य ही आनन्द की प्राप्ति है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि हम किसी के खिलाफ राजनीति करने नहीं आए हैं वरन हम राष्ट्रहित में जो है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्र की अस्मिता एवं अखण्डता को बचाए रखने के लिए परिषद् हमेशा से कृत्संकल्प है। भारतवर्ष में बहुत सारी समस्याएँ आज़ादी के समय से रही हैं तथा परिषद् ने अपना योगदान हर जगह दिया है। आज के दौर में जिस तरह से राष्ट्रविरोधी ताकतों ने विश्वविद्यालयों को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का अड्डा बना रखा है, यह देश के लिए चिन्ता का विषय है।



परिषद् ने इन राष्ट्रविरोधी ताकतों के मंसूबे को नाकाम करने का काम किया है। विद्यार्थी परिषद् विद्यार्थियों का समूहमात्र ही नहीं है वरन उन्हें सच्चरित्र बनाने का प्रयास कर रहा है, देश तथा देश एवं संस्कृति से जोड़ रहा है एवं देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कृत्संकल्प है। राष्ट्र का आधार उसकी संस्कृति ही हो सकती है, अतः उसकी पहचान आवश्यक है।

इस अवसर पर अभावपि के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि जिस तरह से जे. एन. यू. एवं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रविरोधी वामपंथी आज आंबेडकर जी का चेहरा इस्तेमाल करके नये तरीके से आंबेडकर जी का मुखौटा ओढ़कर अपनी राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, उसको उजागर करने का दायित्व परिषद् का है। परिषद् की कार्यप्रणाली अनूठी है जिसमें किसी भी कार्यकर्ता को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है।



अमेरिका में ट्रम्प सरकार और भारत पर प्रभाव

विजय कुमार

तमाम जद्दोजहद ओपीनियन पोल लेफ्ट लिबरल मीडिया द्वारा विरोध के बावजूद डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने 20 जनवरी, 2017 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। यह जीत सही मायने में अमेरिका की आम जनता की जीत है जिन्होंने अपने रोजगार, आत्मसम्मान और अमेरिका की खोई हुई अस्मिता को वापस पाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को वोट किया। यह चुनाव-परिणाम डेमोक्रेटिक पार्टी के कुलीन वर्ग, बिकाऊ मीडिया, छद्म धर्मनिरपेक्ष समूह के ऊपर करारा तमाचा है जो आम अमेरिकी नागरिकों के हित की रक्षा करने में असफल रहे। इस चुनाव में हिंदू-अमेरिकी लोगों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 'अबकी बार ट्रम्प सरकार' का नारा भी खासा प्रचलित हुआ।

इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव शुरू से विवादों में घिरा रहा। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने एक दूसरे पर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और

व्यक्तिगत हमले किये। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का अमेरिकी चुनाव-प्रचार सबसे निचले स्तर का रहा। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी नागरिकों के रोजगार की समस्या को बड़ी मजबूती से उठाया और आठ साल के डेमोक्रेटिक शासन पर हमला बोला, साथ ही साथ मैक्सिको-अमेरिकी सीमा पर दीवार खड़ी करने की बात कही, क्योंकि मैक्सिकन लोग गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में भारी संख्या में आते हैं, साथ-ही-साथ बहुत कम वेतन में काम करते हैं, जिससे आम अमेरिकी नागरिकों के रोजगार पर खासा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने चुनाव-प्रचार में 25 मिलियन नयी नौकरियाँ पैदा करने का वादा किया। इस्लामी आतंकवाद (आईएसआईएस) के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार करने की बात कही, साथ-ही-साथ ओबामा-प्रशासन के इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की आलोचना की। ट्रम्प ने ओबामा-प्रशासन द्वारा की गई ईरान पारमाणविक समझौते की आलोचना की और कहा कि यह समझौता अमेरिका के मध्य-पूर्वी मित्र और इजराइल के हितों के विरुद्ध था। ट्रम्प ने नाटो की प्रासंगिकता पूर्वी एशियाई देशों को दी जानेवाली सुरक्षा तथा टी.पी.पी. (ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप) पर सवाल खड़े किये

ऐसे थे अपने दीनदयाल जी

सुशील कुमार

इस बार का प्रसंग दीनदयाल जी की संघ, संघ की कार्य-पद्धति, विशेषकर शाखा पर गहरी निष्ठा को रेखांकित करता है। हमारा सार्वजनिक क्षेत्र में कितना ही बड़ा स्थान हो, हम कितने ही व्यस्त हो, उसमें से कैसे रास्ता निकालना यह इस संस्मरण का सारांश है। संघ शाखा से इतर अन्य कामों में लगे संघ के कार्यकर्ता इससे सीख सकते हैं।

उस दिन जनसंघ के उस प्रांतीय अधिवेशन का खुला समारोप सायंकाल ही होने के कारण हमलोगों ने अपनी सायं शाखा सुबह लगाकर अपनी प्रार्थना सम्पन्न कर ली थी। क्योंकि हम सब स्वयंसेवक उस खुले अधिवेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भाषण सुनने को लालायित थे। उनके भाषण और शाखा का समय एक ही होने के कारण ऐसी तात्कालिक व्यवस्था अपने ही मन से हमलोगों ने कर ली थी। हम सभी अच्छी संख्या में उस दिन संघस्थान के बजाए सभास्थल पर बैठे, पंडित जी के पूर्व वक्ता मिर्च-मसाला लगाकर चटकारे ले-ले कर राजनीतिक भाषण दे रहे थे। तभी दो बाल स्वयंसेवक दौड़ते-हांफते, हमें खोजते हमारे पास पहुँचे और बोलने लगे 'भैयाजी, भैयाजी! दो बड़े-बड़े आदमी एक दुबले-पतले ठिगने से और दूसरे मोटे-ताजे तोंदवाले हमारे संघस्थान में आए हुए हैं। हमें खेलने से रोककर पूछ रहे थे कि यहाँ शाखा कहाँ लगती है, भई! हम तो प्रार्थना करने बड़ी दूर गाँव से आए हुए हैं।' हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कौन स्वयंसेवक हैं जो पूछते-पूछते संघस्थान पहुँच गये।

मैं तत्काल उठा और अपने दो स्वयंसेवकों को लेकर पहुँच गया रेलवे स्टेशन के निकटस्थ उस संघ स्थान पर जहाँ वे दोनों नवागंतुक स्वयंसेवक आपस में बतियाते चहलकदमी कर रहे थे। देखा, पहचाना—एक दुबले-पतले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और दूसरे मोटे-ताजे पंडित गिरिराज किशोर कपूर। एक जनसंघ के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री और दूसरे मध्य प्रदेश के तत्कालीन प्रान्ताध्यक्ष। सामान्य शिष्टाचार सहित



परिचयोपरान्त पंडित दीनदयाल जी ने पूछा— 'आज क्या शाखा नहीं लगेगी? हमारी प्रार्थना नहीं हुई है आज, इसलिए पूछते-पूछते चले आए संघस्थान।' दरअसल पंडित जी जहाँ भी जाते थे वहाँ शाखा अवश्यमेव पहुँचते थे। वे प्रतिदिन संघ की प्रार्थना करने के आग्रही थे। मैंने कहा— 'हम सबकी इच्छा आपका भाषण सुनने की थी। चूंकि शाखा और भाषण का समय एक ही था और जनसंघ में कार्यरत अपने स्वयंसेवकों का भी आग्रह था कि सभा में अच्छी-खासी उपस्थिति होनी चाहिए, इसलिए हम लोंगों ने निर्णयानुसार आज प्रातःकाल ही शाखा लगा ली।'

परिषद्-गतिविधियाँ



दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ एवं राष्ट्रीय कला मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम 'मदारी' में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करती छात्राएँ



केरल प्रांत छात्रा वर्ग में सहभागी छात्राएँ

स्वामी विवेकानन्द जयन्ती-2017 की झलकियाँ



अरुणाचल प्रदेश में स्वामी विवेकानन्द जयन्ती पर निकली रैली



ईशान्य, मुम्बई विभाग में स्वामी विवेकानन्द जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता